

SHERKOTT
CHOICE OF MILLIONS®
HARDWARE & PAINT TOOLS
www.charminarbrush.com
BEST
SHERKOTT
9440297101
ABRASIVE WATER PAPER

वर्ष-28 अंक : 265 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) मार्गशीर्ष शु.2 2080 गुरुवार, 14 दिसंबर-2023

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH



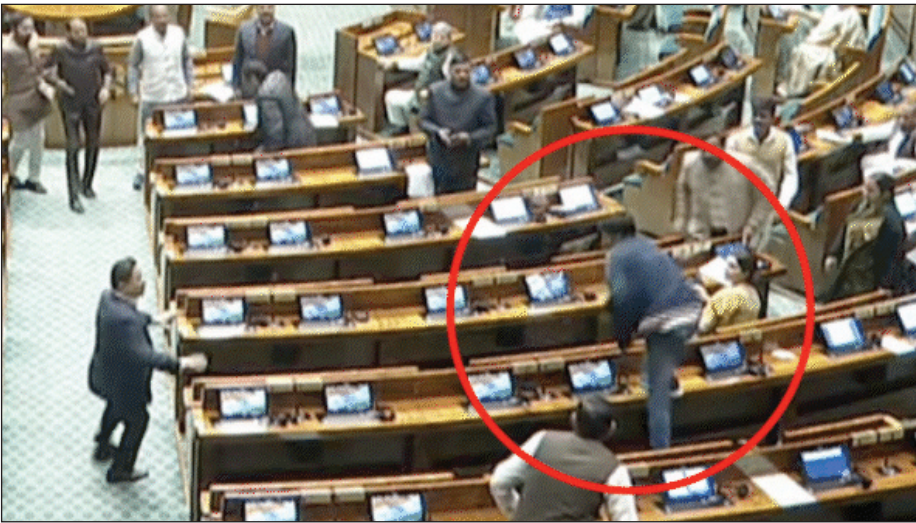
epaper.vaartha.com

नोकास इन्हेलर
सर्दी, जुकाम और बंद नाक का अचूक उपाय
₹60/- only
From the makers of MY Dr.
For WhatsApp Consultation 79003 79008

संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा धराशायी

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। वे सदन की बेंच पर कूदने लगे। युवकों ने जूते में कुछ स्प्रे छिपा रखा था। उसे निकालकर स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में अफरा-तफरी का माहौल था। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने बताया कि मैंने उसे सबसे पहले पकड़ा। कुछ ने दोनों की पिटाई भी की। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। इसे देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर, 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी।

कुल 4 लोग थे, दो सदन के अंदर और दो बाहर बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद विजितर पास पर सदन में आए थे। वहीं, सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। इनका नाम अमोल और नीलम है। इनके पास से कोई फोन या बैग बरामद नहीं हुआ। बाहर से गिरफ्तार हुए दोनों लोगों का दावा है कि खुद से संसद पहुंचे और उनका किसी संगठन से ताल्लुक नहीं है। नीलम ने नारेबाजी की। कहा, 'तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान बचाओ। मणिपुर को इसाफ



दिलाओ। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। जय भीम, जय भारत।' यह घटना दोपहर एक बजे की है। इसके बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। आते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा- अभी हुई घटना सबकी चिंता का विषय है। इसकी जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआती जांच में वह साधारण धुआं था। डिटेल

जांच के नतीजे आने पर सबको इससे अवगत कराया जाएगा। इस मामले पर डीएमके सांसद टीआर बालू ने सवाल पूछना चाहा, तो स्पीकर ने कहा कि दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनके पास मिले सामान को जब्त कर लिया गया है। जो दो लोग सदन के बाहर थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2001 में संसद पर हमला हुआ था। आज फिर इसी दिन हमला हुआ है। क्या इससे साबित होता है कि सुरक्षा में चूक हुई है।

खगेन मुर्मू ने कहा-मुझे लगा कोई आ रहा है लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने बताया, 'मैं स्पीच दे रहा था। तभी दाईं तरफ से आवाज आई तो मुझे पता चला कि कोई आ रहा है। सामने की तरफ से सांसद और सिक्स्योरिटी गार्ड पकड़ो-पकड़ो चिल्लाने लगे। वे हाथ में कुछ लिए थे, जिससे धुआं निकल रहा था। सदन धुए से भर गया। युवक सीधे स्पीकर की तरफ जा रहे थे। तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगा रहे थे। उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे।' कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने गैलरी में कूद शख्स को पकड़ा। उनके हाथ में भी पीला रंग लग गया। **कार्ति चिंदंबरम (कांग्रेस)-** अचानक दो

लोग विजितर गैलरी से लोकसभा में कूदे। दोनों की उम्र करीब 20 साल है। ये लोग कनस्तर लिए हुए थे। इन कनस्तरों में पीले रंग की गैस निकल रही थी। दोनों में से एक व्यक्ति दौड़कर स्पीकर की चेयर के सामने पहुंच गया था। वे कोई नारा लगा रहे थे। आशंका है कि ये गैस जहरीली हो सकती है। 13 दिसंबर 2001 के बाद ये फिर संसद की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है।

अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस)- दो लोग गैलरी से कूदे। उन्होंने कुछ फेंका, जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और फिर सुरक्षा अधिकारियों ने बाहर कर दिया। यह सुरक्षा में चूक तब हुई है, जब संसद हमले की 22वीं बरसी है।

सुदीप बंदोपाध्याय (टीएमसी)-ये डरावना अनुभव था। संसद में अचानक दो लोग कूद गए। उनका मकसद क्या था, कोई नहीं जानता। वो धमाका कर सकते थे, किसी को गोली मार सकते थे। हम सभी तुरंत सदन से बाहर चले गए, लेकिन यह एक सुरक्षा चूक थी। वे धुआं छोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे प्रवेश कर सकते थे? शिवसेना (उद्धव गुट) सांसद अरविंद सावंत- लोकसभा में अचानक दो लोग गैलरी से कूद पड़े। फिर दोनों बेंच के ऊपर से कूदने लगे। एक ने अपना जूता उतार लिया। सांसदों ने उसे पकड़ लिया। तभी अचानक पीले रंग की गैस निकलने लगी। शायद उनके जूते से गैस निकल रही थी। **>14**

बर्द्धमान रेलवे स्टेशन पर पानी की टंकी गिरी

ट्रेन का इंतजार कर रहे तीन पैसेंजर्स की मौत, 15 घायल-3 की हालत गंभीर

कोलकाता, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान रेलवे स्टेशन पर बुधवार (13 दिसंबर) को पानी की टंकी प्लेटफॉर्म पर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर है। सभी लोग प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

घटना के बाद रेलवे के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और टंकी को नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की

कोशिश की। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है।

रेलवे ने बताया कि पानी की टंकी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर गिरी। टंकी का कुछ हिस्सा रेलवे ट्रैक पर भी गिरा। इससे वहां पड़े पत्थर उछलकर पैसेंजर्स को लग गए। इससे भी कई लोग घायल हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर फिलहाल रेल सेवाएं रोक दी गई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और

4 पर ट्रेन चल रही हैं।

रेलवे ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया

इस घटना के बाद रेलवे ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पानी के टंकी की क्षमता 53 हजार गैलन की है। यह टंकी काफी पुराना था। जिस वजह से इसके टूटने की आशंका जताई जा रही है।

महादेव बेटिंग ऐप का मालिक रवि उप्पल यूआई में गिरफ्तार

जल्द भारत लाने की तैयारी-मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जांच कर रही है

रायपुर, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि भारत में वांटेड है। भारतीय एजेंसियां वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। रवि को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर इंग्लैंड में रवि उप्पल के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। माना जा रहा है कि इसके बाद सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिल गई है। महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा था। इसे बीजेपी ने अपने आरोप पत्र और चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। पार्टी ने सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी महादेव ऐप जांच कर रही है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस

भी जांच में जुटी है। ईडी ने अक्टूबर में रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के सामने उप्पल और उसके पार्टनर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने 2 महीने पहले महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी कर 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। रवि उप्पल साथी सौरभ चंद्राकर के साथ यूएई में रह रहा था। केंद्र सरकार ने 1 महीने पहले ही महादेव सट्टेबाजी ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी।

हालांकि, शुरुआत में इस वेबसाइट के कम यूजर्स थे और इससे काफी कम कमाई होती थी। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। दानिश अली ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 21 साल पहले इसी दिन (13 दिसंबर) संसद पर हुए हमले की दिल दहला देने वाली याद दिलाते हुए, एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा सांसदों के क्षेत्र में कूद गया। इस उल्लंघन से सांसदों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वह शख्स भाजपा सांसद का मेहमान था।

लोकसभा में कूदने वाला युवक भाजपा सांसद का मेहमान था : दानिश अली

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। बसपा से निष्कासित लोकसभा सांसद दानिश अली ने दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदने वाले युवकों में से एक युवक के लोकसभा के पास की तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर यह दावा किया है कि वह व्यक्ति भाजपा सांसद का मेहमान था। उस व्यक्ति का पास भाजपा सांसद की सिफारिश पर बनाया गया था।

दानिश अली ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 21 साल पहले इसी दिन (13 दिसंबर) संसद पर हुए हमले की दिल दहला देने वाली याद दिलाते हुए, एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा सांसदों के क्षेत्र में कूद गया। इस उल्लंघन से सांसदों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वह शख्स भाजपा सांसद का मेहमान था।

संसद हमले के 22 साल : उपराष्ट्रपति-स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि

मोदी-शाह, खड़गे और सोनिया मौजूद रहे, पीएम शहीदों के परिवार से भी मिले



दे रहे हैं। उनका साहस और बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा- 2001 में हमारी संसद पर हुए हमले के दौरान शहीद हुए साहसी सुरक्षाकर्मियों के बलिदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आतंकवाद पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक खतरा बना हुआ है। इसे खत्म करने के लिए

सफेद ऍबेसेडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर-12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्स्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। ये सब देखकर सिक्स्योरिटी गार्ड ने उस ऍबेसेडर कार के पीछे दौड़ लगा दी। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। इसके बाद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के पास एके-47 और हैंडग्रेनेड थे। इसके बाद संसद भवन में मौजूद सीआरपीएफ की बटालियन अलर्ट हो गई। उस वक्त सदन में देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर-1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्स्योरिटी फोर्स ने उसे वहीं मार गिराया। **>14**



और जुर्माना लगाने का प्रावधान था। ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ न तो केस दर्ज होता था और न ही उसे सजा देने का प्रावधान था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा सकता। जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। एडल्ट्री की तरह नए बिल में सेम सेक्स या अननेचुरल सेक्स को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। हालांकि उसके बाद देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर मांग उठने लगी।



भूमि संबंधी विवादों के निपटारे हेतु विशेष समिति : रेवंत रेड्डी

मुख्यमंत्री ने भूमि विवाद पर समीक्षा बैठक की



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री ने आज डॉ. बीआर अंबेडकर सचिवालय में राज्य में धरणी प्रदर्शन और भूमि संबंधी मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क, चिकित्सा, स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दामोदरा राजा नरसिम्हा, राजस्व, आवास, सूचना मंत्री पोंगुलेटी

श्रीनिवास रेड्डी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी, राजस्व विभाग के मुख्य सचिव नवीन मित्तल, अन्य उच्चाधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा इस समिति का गठन कोनेरू रंगा राव समिति की तरह ही किया जाना चाहिए। इस समिति के प्रस्ताव सुझाए जाएं

ताकि भूमि संबंधी विवादों का स्थायी समाधान हो सके। इस समिति में मंत्रियों के अलावा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, किसानों के प्रतिनिधि और भूमि संबंधी कानूनों के विशेषज्ञ सदस्य हों। मुख्यमंत्री ने सीएस को धरणी की शुरुआत से अब तक लिए गए निर्णयों पर एक विस्तृत रिपोर्ट

प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस बैठक में सीएमओ अधिकारी शिवधर रेड्डी, शेपाद्री और शाह-नवाज कासिम ने भाग लिया, महबूबनगर के विधायक येन्म श्रीनिवास रेड्डी, किसानों के प्रतिनिधि कोडंडा रेड्डी, वेम रंजेंद्र रेड्डी, संपत कुमार रथेविन्नु एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे और अपने विचार व्यक्त किए।

गुप्ता ने सीएम रेवंत का स्वागत किया किया

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। विधान परिषद के अध्यक्ष गुप्ता सुखेंद्र रेड्डी ने बुधवार को विधानसभा में अपने कक्ष में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अभिनंदन किया। गुप्ता सुखेंद्र रेड्डी ने मुख्यमंत्री का अपने कक्ष में स्वागत किया और उन्हें शाल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे कांग्रेस विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार के समर्थन में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधानसभा का दौरा किया। बाद में, रेवंत रेड्डी ने कार्डसिल हॉल का भी दौरा किया और इमारत की भौतिक संरचना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री श्रीधर बाबू, सीताका, कांडा सुरेखा और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और कुछ विधायक भी थे।



दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा गोशामहल पुलिस ग्राउण्ड में जारी श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अन्तर्गत प्रातः बेला में आयोजित योग शिविर एवं मध्यान में आयुर्वेदिक जांच और परामर्श शिविर शिविर में भाग लेते हुए समाज बंधु।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से फोन पर बात की

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से फोन पर बातलाप किया।

इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार 13 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी को फोन कर कहा कि, केंद्र सरकार से तेलंगाना को प्राप्त होनेवाले फंड्स और अन्य मुद्दों पर आपसी सहयोग करें। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय मंत्री से जल्द ही केंद्र सरकार के प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित करने की अपील की। इस पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सकारात्मक रुख अपनाया।

माओवादियों ने वेंग और भवानी की रिहाई की मांग की

कोतागुडम, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने पार्टी नेता वेंग (डी गंगाधर राव) और उनकी पत्नी भवानी की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। बुधवार को यहां मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 75 वर्षीय वेंग दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सचिवालय और केंद्रीय तकनीकी समिति के सदस्य रह चुके हैं। 60 वर्षीय भवानी ने डीके एसजेडसी के तकनीकी विभाग में कंपनी पार्टी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। माओवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 दिसंबर को मंचेरियल जिले के जयपुर मंडल के इंदाराम गांव से तेलंगाना एसआईबी की एक विशेष टीम द्वारा बृहत् आरोपों में गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया।

वे वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले कुछ महीनों से इंदाराम गांव में रह रहे थे। माओवादी सेंट्रल कमेटी ने लोगों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार और नागरिक अधिकार संगठनों से अपील की है कि वे उन्हें जेल में सभी आवश्यक सुविधाएं और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग करें।

CLASSIFIEDS CHANGE OF NAME

I, No. 14808806M (Dvr MT), GADDAM CHANDRA SEKHAR REDDY, residing at 14-3-12, Nallagutta, Sydarpuram, Kadri Sri Satya Sai District, Andhra Pradesh-515991, having changed my daughter's name from G. NAVAYA her date of birth: 31-01-2007 (as per birth POR/RCSR) to GADDAM NAVYA, date of birth 14-01-2007 (proposed new name & date of birth) Vide Affidavit 28 Nov.2023 J Sudershana Chary Advocate & Notary City Civil Court Secunderabad Hyd -500015, Telangana

आवधान
पाठकों को सूचित किया जाता है कि वर्गीकृत विज्ञापन का प्रतिपादन करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। विज्ञापनदाता ने दावा कर रहे हैं या कह रहे हैं, उन बातों से दैनिक समाचार पत्र (स्वतंत्र वार्ता) का किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है।

नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : अविनाश मोहंती

साइबराबाद के नए पुलिस आयुक्त ने कार्यभार संभाला



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। साइबराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए, अविनाश मोहंती ने

स्टीफन रवीन्द्र से पदभार ग्रहण किया, जिनका तबादला कर दिया गया और उन्हें डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी कानून का शासन बनाए रखना और हमसे संपर्क करने वाले हर व्यक्ति के प्रति निष्पक्ष रहना है।" 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी, अविनाश मोहंती, जो आयुक्त पद पर पदोन्नत होने से पहले साइबराबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि साइबराबाद में अधिक साइबर और आर्थिक धोखाधड़ी अपराध के मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा, "सभी जांच पूरी व्यावसायिकता के साथ निष्पक्ष और उचित तरीके से की जाएगी।" यातायात के मोर्चे

पर, मोहंती ने कहा कि यातायात पुलिस विशेष रूप से साइबराबाद के उच्च यातायात घनत्व वाले क्षेत्रों में यातायात संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस साइबराबाद में अनेक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और ड्रग्स, महिला तस्करी, भूमि माफिया और आर्थिक अपराधों जैसे संगठित अपराधों में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मोहंती ने पहले साइबराबाद में डीसीपी (यातायात) के रूप में काम किया था और बाद में उन्हें हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त (जासूसी विभाग) के रूप में काम किया।

विधायक प्रसाद कुमार, सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष चुने गये

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। विधायक प्रसाद कुमार, सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष चुने गये हैं। इस संदर्भ में, तेलंगाना सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने विस्तार से बताया कि, इस मामले में शाम समाप्त नामांकन प्रक्रिया में प्रसाद कुमार का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ क्योंकि केवल एक ही नामांकन हुआ था। इस बारे में प्रसाद कुमार ने बुधवार 13 दिसंबर की सुबह अपना नामांकन पत्र विधानसभा सचिव को सौंपा। नामांकन दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क सहित कई मंत्रीगण, बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर, कोतागुडम विधायक के. सांबशिवराव और अन्य उपस्थित हुए।



बुधवार को केबीआर पार्क में गणेश जी पूजा-अर्चना करते हुए गोपाल बल्लदवा, विठ्ठलदास अग्रवाल, शंकरलाल, विजय कुमार अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, सुरेश सौए, श्रीनिवास, सुरेंद्र मोहन व अन्य।

हैदराबाद में खुलेगा वैल्यू जोन का नया आउटलेट

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। वैल्यू जोन नगर में सीधे आपके दरवाजे पर खरीददारी क्रांति ला रहा है। इस गतिशील शहर के केंद्र में, खुद्रा क्षेत्र में एक नया अध्याय खुल रहा है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां खरीदारी सिर्फ चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनुभव है संजोए -वैल्यू जोन का नया आउटलेट मॉल यही वादा करता है। यह सिर्फ एक और विकास नहीं है। यह एक वैश्विक शहर के रूप में हैदराबाद के विकास का प्रमाण है। व्यस्त राजमार्गों के किनारे स्थित, ये आउटलेट मॉल सिर्फ दुकानें नहीं हैं, वे खरीददारी के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। जैसे-जैसे भारत अपने प्रभावशाली राजमार्गों के साथ आगे बढ़ रहा है, ये मॉल खरीदारी करने वालों के लिए नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। आउटलेट मॉल की अवधारणा, हालांकि भारत के लिए नई है, एक वैश्विक घटना रही है। वैल्यू जोन, अपने रणनीतिक स्थान और विविध पेशकशों के साथ, इस विकसित परिदृश्य में एक मील का पथर बनने के लिए तैयार है। वैल्यू जोन महज एक शॉपिंग सेंटर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जिसे हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर, लुभाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई ब्रांड 40: से शुरू होने वाली छूट की पेशकश कर रहे हैं, यह एक सपने के सच होने जैसा है। लेकिन यह सिर्फ छूट ही नहीं है जो लोगों को आकर्षित करती है यह एक ऐसे स्थान पर रहने का समय और सीधा पूर्ण अनुभव है जो उनकी जरूरतों को समझता है और उन्हें पूरा करता है। वैल्यू जोन के साथ, खुद्रा क्षेत्र का भविष्य न केवल उज्ज्वल है। यह जीवन और संभावनाओं से भरपूर है। यह एक ऐसी जगह है जहां परिवार एक साथ आते हैं, और जहां हर खरीदार को संजोने के लिए कुछ न कुछ मिलता है। हैदराबाद-सोलापूर राजमार्ग आईटी हब से सिर्फ 18 किमी दूर, आप हैदराबाद के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित पाटनचेर देखेंगे।

शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त उपाय होंगे : सुधीर बाबू

सीपी राचकोंडा देंगे कर्मचारी कल्याण को उच्च प्राथमिकता

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। नरेंद्रमेट में राचकोंडा आयुक्तालय के कार्यालय में राचकोंडा आयुक्तालय के नए आयुक्त सुधीर बाबू के रूप में कार्यभार संभाला। कई अधिकारियों एवं कार्यालय कर्मियों ने फूलों के गुलदस्ते देकर आयुक्त का स्वागत किया। इस मौके पर राचकोंडा में कार्यरत डीसीपी, एसीपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को उनकी योग्यता पर भरोसा कर जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राचकोंडा में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या को रोकने और अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और जल्द सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि सिविल, एआर, सख्त कदम उठाए जाएंगे और लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए कई



की देखभाल के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और शी टीमां को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नशीली दवाओं की आपूर्ति और उपयोग पर नकल कसंगे और युवाओं को नशे का शिकार होने से रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए कई

कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व में राचकोंडा के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में काम करने के अनुभव के साथ, उन्हें राचकोंडा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा उपद्रवी बदमाशों पर समय-समय पर निगरानी रखी जायेगी। उन्होंने कहा कि शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की भी सलाह ली जायेगी तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाले अधिकारियों को सहायता प्रदान की जायेगी। कार्यक्रम में राचकोंडा एडिशनल सीपी तरुण जोशी, मल्काजगिरी डीसीपी धारावाट जानकी, महेश्वर डीसीपी श्रीनिवास, एलबीनगर डीसीपी साईश्री, महिला सुरक्षा डीसीपी उषा विश्वनाथन आईपीएस, सडक सुरक्षा डीसीपी श्रीबाला, डीसीपी क्राइम अरविंद, डीसीपी एडमिन इंद्रिा और अन्य ने भाग लिया।

कागजनगर

तहसीलदार का तबादला

सिरपुर कागजनगर, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। कागजनगर के तहसीलदार के. श्रीपाल रेड्डी को कोटाला मंडल के तहसीलदार के रूप में स्थानांतरित किया गया है। जिला कलेक्टर बोरार्के हेमंत सहदेव राव ने एक स्थानांतरण आदेश जारी कर कोटाला मंडल के तहसीलदार के रूप में कार्यरत टी किर्ण कुमार को कागज नगर तहसीलदार के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। आदेश की कॉपी कागजनगर के आरडीओ, डीटीओ और एसटीओ को भी भेज दी गयी है।

दक्षिण मध्य रेलवे	
<div>  <div> <div>हैदराबाद डिवीजन में वाणिज्यिक संविदाओं के प्रति ई-नीलामी सूचना</div> <div> <div>वॉय/सी ई-नीलामी/एचवायबी/2023-24 दि.11.12.2023</div> <div>हैदराबाद डिवीजन में वाणिज्यिक संविदाओं के प्रति ई-नीलामी सूचना</div> </div> </div> </div>	
<p>हैदराबाद डिवीजन में वाणिज्यिक आय संविदाओं अथवा कमर्शियल एग्रीमेंट कांटाक्ट्स एवं एनएफआर संविदाओं के लिए ई-नीलामी लागू की है। तदनुसार, एचवायबी डिवीजन ने निम्न श्रेणियों के लिए ई-नीलामी संसाधित की है।</p>	
क्रम सं. 01 श्रेणी: ट्रेन एक्स्टीरियर या रेल का बाहरी भाग (फुल पैक या पूरा अग्र भाग), सूची सं. एचवायबी-पीयुबी-29, कार्य विवरण: ट्रेन नं.12797/12798 काचीगुडा-चिरूर-काचीगुडा वेंकटगिरी एक्सप्रेस वाया कर्नूल सिटी, दोनों के लिए विभिन्न रैपिड द्वारा एडवर्डजॉन राहडस वा विज्ञापन अनुबंध प्रदान करना। नीलामी की तिथि: 23.12.2023, नीलामी शुरू समय: सुबह 11.00 बजे, नीलामी बंद समय: सुबह 11.30 बजे	PUBLIC TENDER
क्रम सं.02, श्रेणी: एडवर्डजॉन आउट अग्र होम या घर के बाहर विज्ञापन व्यस्तता, सूची सं. एचवायबी-पीयुबी-29, कार्य विवरण: कूटर-5 इवेंस में शामिल निम्न 5.1एलसी नं.165(एलसी-शुभमआराय), 5.2 एलसी नं. 172(केके-डोबी), 5.3एलसी नं.179(केके-डोबी), 5.4 एलसी नं.180(डोबी-बीएसएस), 5.5 एलसी नं.182(डोबी-बीएसएस), 5.6 एलसी नं.188(बीएसएस-एचबीटी) नीलामी तिथि: 23.12.2023, नीलामी शुरू समय: सुबह 11.00 बजे, नीलामी बंद समय: सुबह 11.30 बजे	
क्रम सं. 03 श्रेणी: मिस्क. स्टेटिक सर्विसेज या विविध स्थैतिक सेवाएं, सूची सं. एचवायबी-केसीजी-एनएसएस-01, कार्य विवरण: हैदराबाद डिवीजन के काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर सीपीजी पाइस की व्यवस्था। नीलामी तिथि: 26.12.2023, नीलामी शुरू समय: सुबह 11.30 बजे, नीलामी बंद समय: दोप. 12.00 बजे	
A1855	वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, हैदराबाद

16 साल बाद कांग्रेस सरकार में बिलासपुर को मिला मंत्री पद

बिलासपुर, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। कांग्रेस सरकार बनने के एक साल के इंतजार के बाद जिला बिलासपुर को सुक्खू मंत्रिमंडल में जगह मिल ही गई। जिले से कांग्रेस के एकमात्र विधायक और सीएम सुक्खू के करीबी राजेश धर्माणी ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस सरकार में 16 साल बाद बिलासपुर को मंत्री पद मिला है। 2007 तक नयनादेवी से रामप्ताल ठाकुर बतौर वन मंत्री रहे। सरकार के एक साल के जशन के कार्यक्रम के बाद सोमवार रात को ही तय हो गया था कि धर्माणी को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा। सुबह से ही उनके घर पर समर्थकों की भीड़ बधाई देने के लिए जुट गई थी। धर्माणी के पास संगठन में भी काम करने का अच्छा खासा अनुभव है।

2012 में जीत हासिल करने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार में धर्माणी को मुख्य संसदीय सचिव का पद दिया गया। वीरभद्र सिंह ने उन्हें वन विभाग के साथ अटैच किया था। वीरभद्र सिंह

जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का है टारगेट

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को पार्टी की एक बड़ी बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों



और राजेश धर्माणी के बीच हमेशा सियासी शीत युद्ध चलता रहा। दोनों नेताओं ने कभी एक-दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन धर्माणी खुद को पद के साथ शक्तियां न दिए जाने पर अकसर नाराज रहे। धर्माणी ने नाराज होकर पहले 2 अक्टूबर 2013 को मुख्य संसदीय सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में नुकसान न हो, इसके लिए उन्होंने 4 अक्टूबर 2014 को इस्तीफा वापस ले लिया था। 10 मई 2014 को एक बार फिर सीपीएस का पद छोड़ दिया था। धर्माणी हमेशा अपने सिद्धांतों के पक्के रहे, उन्होंने सीपीएस रहते हुए भी सरकारी गाड़ी का

इस्तेमाल नहीं किया। 2 अप्रैल 1972 को बिलासपुर के घुमारवीं में जन्मे राजेश धर्माणी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला चुवाड़ी से पूरी की। घुमारवीं से आगे की स्कूली पढ़ाई पूरी की। एनआईटी हमीरपुर से बीटेक सिविल की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने एमबीए भी की। राजेश धर्माणी प्रदेश कांग्रेस कमेटی के सचिव, युथ कांग्रेस के महासचिव और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह संवेदना चैरिटेबल सोसायटी के फाउंडर मेंबर भी हैं। घुमारवीं सीट से राजेश धर्माणी ने 2007, 2012 में लगातार दो बार जीत हासिल की। इस बार 2022 में तीसरी बार जीत हासिल की है।



पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने नवंबर में पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना

और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए। जिसके नतीजे इस महीने दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए गए। पांच में से हिंदी पट्टी वाले तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की और तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को मौका दिया। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का ये बड़ा कदम बताया जा रहा है।

आप को झटका, राज शौकीन समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल, राहुल गांधी को लेकर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। दिल्ली आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। आप की संस्थापक सदस्य और वर्तमान में ज्वाइंट स्टेट सेक्रेटरी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य राज शौकीन कांग्रेस अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गईं। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली ने पार्टी के पट्टा पहना उन्हें देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल कराया। साथ ही कहा कि राज शौकीन का कांग्रेस में स्वागत है। राज का कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज के साथ पार्टी से जुड़ने वाले आपके सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं

का आभार। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आप की फाउंडर मेंबर और वर्तमान में ज्वाइंट स्टेट सेक्रेटरी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य राज शौकीन ने प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को मौजूदगी में कांग्रेस परिवार में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में इस समय किस तरह का माहौल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। देशभर में मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी के देश के प्रति प्रेम, लगाव और समर्पण से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ रही हूं।

शादी से लौट रहे 'टीएमसी नेता के दामाद को बदमाशों ने मारी गोली, फिर धारदार हथियार से किया वार

कोलकाता, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में स्थानीय टीएमसी नेता के दामाद की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक 30 वर्षीय तन्मय सरकार को बदमाशों ने मंगलवार को उस वक्त रोका, जब वह अपनी बाइक से एक शादी से लौट रहे थे और फिर करीब से गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपियों ने मौके से भागने से पहले तन्मय सरकार पर धारदार हथियार से हमला भी किया। तन्मय सरकार को पहले स्थानीय इटाहार अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया।

भाजपा सांसद किरण खेर पर गंभीर आरोप शरत्स को दी जान से मारने की धमकी, कारोबारी को मिली पुलिस सुरक्षा



सलारिया के संपर्क में आए। उन्होंने दावा किया कि खेर ने उन्हें निवेश के लिए 8 करोड़ रुपये दिए थे और वह पहले ही दो करोड़ रुपये लौटा चुके हैं और शेष लौटाना बाकी है। याचिका में कहा गया है कि बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण, याचिकाकर्ता ने निवेश पर मूनाफा अर्जित करने और पैसे लौटाने के लिए समय मांगा। इसमें कहा गया है कि उन्हें तुरंत व्याज सहित पैसे लौटाने की धमकी दी गई और खेर तथा उनके सहयोगी द्वारा लगातार

पेशाना किया जा रहा है। लोक अभियोजक मनीष बंसल ने अदालत के समक्ष कहा कि याचिकाकर्ता या उनकी पत्नी या उनकी नाबालिग बेटियों की ओर से किसी भी थाने में इस संबंध में कोई शिकायत नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी धमकी के मामले में, ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 है, लेकिन न तो याचिकाकर्ता और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया है। याचिकाकर्ता के वकील सिद्ध

ने दलील दी कि ‘‘प्रतिवादी नंबर दो (खेर) की ‘प्रोफाइल’ को देखते हुए, यदि वे सीधे इस अदालत में आए हैं, तो यह उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।’’ मामले के गुण-दोष और याचिका की विचारणीयता पर टिप्पणी किए बिना, अदालत ने 11 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘आगर यह अदालत फिलहाल उन्हें सुरक्षा नहीं देती है, तो यह संबंधित थाना प्रभारी को एक प्रयोग नहीं करने के समान होगा।’ इसके साथ ही अदालत ने संबंधित पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को एक सप्ताह के लिए याचिकाकर्ता को उचित सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता की अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो सुरक्षा एक सप्ताह से पहले भी हटायी जा सकती है।

अपनी पत्नी को दोस्त के साथ रात बिताने को किया मजबूर, केस दर्ज

बेंगलुरु, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। बेंगलुरु में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ रात बिताने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस घटना को लेकर उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया और उसके साथ मारपीट की। शिकायत के बाद बसवनगुडी महिला पुलिस ने प्रारंभिकी दर्ज की और जांच शुरू की। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी उस पर अपने दोस्त के साथ रात गुजारने का दबाव बना रहा था। बसवनगुडी इलाके के रहने वाले आरोपी ने एक साल पहले पीड़िता से शादी की थी। उसने कथित तौर पर अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए उसे 10 लाख रुपये का दहेज लाने के लिए मजबूर किया। पीड़िता ने अक्सर बेवकूफ से पीड़ा जताा था और उसके भाई ने पहले ही 2 लाख रुपये दे दिए थे।

आईवी की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट से पकड़े गए 8 'भगोड़े', विदेश में ले रखी थी पनाह

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। इंटेलीजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आने वाले इमीग्रेशन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से सात भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। इन सभी भगोड़ों के खिलाफ विभिन्न राज्यों द्वारा लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था। सबसे अधिक 4 गिरफ्तारियां दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से की गई हैं। इसके अलावा, अन्य गिरफ्तारियां अमृतसर एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट से की गई हैं। गिरफ्तार किए गए सभी भगोड़ों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर संबंधित विभागों के सूचित कर दिया गया है। पहला मामला, दिल्ली एयरपोर्ट का है।

इमीग्रेशन विभाग ने एयर इंडिया की पेरिस से आने वाली फ्लाइट एआई-142 से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे एएच नंदा को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पहुंचते ही इमीग्रेशन अधिकारियों ने लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे मामले में, इमीग्रेशन विभाग ने मस्कट से दिल्ली पहुंचे अमृतपाल सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ भी एलओजी जारी थी। इसके अलावा, दिल्ली एयरपोर्ट से हांगकांग जाने की कोशिश कर रहे महेंद्र विश्वकर्मा को राजस्थान पुलिस द्वारा जारी एलओसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया

है। वहीं, अमृतसर एयरपोर्ट से क्वालालंपुर जाने की कोशिश कर रहे टीके सेहमी और अमृतपाल सिंह को एलओसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, अहमदाबाद एयरपोर्ट से कमलेश कुमार नामक शख्स को एलओसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह शाहजाह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। इमीग्रेशन विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट से राहुल झा नामक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्रिसेबन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। वहीं, लखनऊ एयरपोर्ट से सलता भाई कारीगर को गिरफ्तार किया गया है, वह मस्कट से लखनऊ पहुंचा था, उसके खिलाफ गुजरात पुलिस ने एलओसी जारी की थी।



हुए हैं, जिनमें से कोई भी वर्तमान में काम पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। आरोपी का हलफनामा पट्टादाता द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अजमेरा ने उन्हें विमान का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी और अदालत के निर्देशों के अनुसार उनका रखरखाव नहीं किया। हलफनामे में लिखा है, वर्तमान अवमानना याचिका सही इरादे से दायर नहीं की गई है और वास्तव में रित याचिकाओं में अंतिम फैसलों को विर्लंबित करने और पटरी से उतारने के एकमात्र उद्देश्य से दायर

की गई है।" उन्होंने अवमानना याचिका की सामग्री को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि कर्मचारियों/कर्मचारियों का वेतन अप्रैल 2023 से नहीं दिया गया था। सीआईआरपी 10 मई 2023 को शुरू होने के बाद, पूर्ववर्ती आईआरपी ने मई 2023 के महीने के वेतन का भुगतान करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार के पास उपलब्ध मौजूदा धन का उपयोग किया था। इसके बाद, जून 2023 के महीने के लिए वेतन भुगतान अगस्त 2023 में कॉर्पोरेट देनदार की चालू

बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: अस्पताल ने सुजय भद्र को आईसीयू से केबिन में स्थानांतरित किया



कोलकाता, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। राज्य सरकार द्वारा संचालित दक्षिण कोलकाता के एसएसकेएम। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र को कार्डिओलॉजी विभाग के आईसीयू से वापस सामान्य केबिन में स्थानांतरित कर दिया है। मामले के जानकार सूत्रों ने बताया कि भद्र की चिकित्सीय स्थिति में सुधार के बाद उन्हें वापस सामान्य केबिन में स्थानांतरित करने का निर्णय रात को लिया गया। यह निर्णय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्डिओलॉजी विभाग के आईसीयू में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के दो सशस्त्र कर्मियों के अलावा

अपने दो अधिकारियों को निगरानी के लिए तैनात करके सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के फैसले के बाद किया गया है। वहीं, मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने एसएसकेएम। से भद्र के कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट (सीएबीजी) के बारे में रिपोर्ट माँगी है ताकि यह समझा जा सके कि इस साल अगस्त में बाईपास सर्जरी होने के बाद आरोपी को चार महीने तक भर्ती क्यों रहना पड़ा। उल्लेखनीय है कि ईडी के अधिकारी मामले की जाँच के सिलसिले में 7 दिसंबर को भद्र की आवाज का नमूना परीक्षण करने से पहले अलिवार्य चिकित्सा जांच के लिए उन्हें कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में केंद्र संचालित ईएसआई अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए एक एम्बुलेंस के साथ एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे थे। हालाँकि, अधिकारियों को खाली हाथ लौटाना पड़ा क्योंकि एसएसकेएम। के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया

एयर इंडिया को देरी से विमान उड़ाना पड़ा भारी अब इन लोगों को देना होगा 2 लाख का हर्जाना



तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। विमान को समय से परिचालन करना हमेशा से एक बड़ी समस्या रहा है। सभी विमान कंपनियों दावा करती हैं कि उनका उड़ान समय से यात्री को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी, लेकिन बहुत कम एयरलाइन ही इस दावे पर खरा उतर पाती हैं। ऐसे में एयर इंडिया को भी उड़ान में देरी करना भारी पड़ा और अब उसे इसकी एवज में यात्रियों को 2 लाख रुपये का हर्जाना देना पड़ेगा।

जानिए क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण

चेन्नई,चेन्नई से कोलकाता और बाद में कोलकाता से डिब्रुगढ़ की यात्रा के लिए चार अलग-अलग हवाई रिटर्निंग टिकट खरीदे थे। तिरुवनंतपुरम-चेन्नई उड़ान को देरी का सामना करना पड़ा, जिससे शिकायतकर्ताओं की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। शिकायतकर्ताओं ने अपने आरोप में कहा कि बेंगलुरु से कोलकाता के लिए सुबह 6 बजे प्रस्थान के एयरलाइन के भरोसे के बावजूद, आधी रात को वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कहा कि इस दौरान एयरलाइन की ओर से जो खाना उपलब्ध कराया गया। वह काफी खराब क्वालिटी का था।

इसके बाद दिल्ली और डिब्रूगढ़ की फ्लाइट भी कोलकाता नहीं पहुंची, जिसके कारण शिकायतकर्ताओं को पेशेजाना का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा को अधूरा ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद जिला फोरम में एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

स्वतंत्र वास्तव

गुरुवार, 14 दिसंबर - 2023

नये चेहरों ने चौंकाया

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की बारी है। तीनों प्रदेशों के सीएम चेहरे को लेकर जिसने भी चुना सबने आश्चर्य व्यक्त किया। तीनों राज्यों के सीएम अनजान से चेहरे वाले ही हैं। इसके पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि वरिष्ठ नेताओं में से किसी को कमान सौंपी जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जयपुर की सांगानेर सीट से पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा ने नाम पर पार्टी हाइकमान की मुहर लग गई तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसे ही चौंकाते वाले निर्णय मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लिए गए। मध्यप्रदेश में तो जितने मुंह उतनी बातें हो रही थीं। काफी लोग भाजपा की विजय के पीछे शिवराज सिंह चौहान के कामकाज और योजनाओं का बड़ा हाथ होने का कयास लगा रहे थे। उनके अलावा केंद्र से मंत्री पद छोड़ कर एमएलए बने नेताओं की भी पुरस्कृत करने की अटकलें चल रही थीं। मगर एमपी में मोहन यादव बाजी मारने में सफल रहे। कमोवेश यही हाल छत्तीसगढ़ में रहा जहां विष्णुदेव साय को सत्ता की चाबी सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की कमान बिल्कुल अनजान से नेताओं को सौंप कर भाजपा नेतृत्व ने लोगों को बिस्मित कर दिया था। लेकिन राजस्थान में भी जब यही काम किया गया तो लोग चर्चा करने लगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की स्टाइल ही यही है। इसके पहले वे गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में ऐसा प्रयोग कर भाजपा को विजय दिलाई है। यदि मोदी ने इस तरह के साहसपूर्ण निर्णय लिया है तो इसकी कुछ वजहें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आमतौर पर राजनीतिक दल नेताओं की वरिष्ठता और अनुभव आदि को ध्यान में रख कर मठाधीश टाइप नेताओं को मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य पदों पर नियुक्ति करते हैं। मगर मोदी के नेतृत्व में भाजपा इस फार्मूले से अलग हटकर काम करती है। मोदी के लिए संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करता है, उसे पुरस्कृत किया जाता है। संगठन में खेमेबंदी करने वालों को एकदम से ठिकाने लगा दिया जाता है। इसी का दंड शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भुगतना पड़ा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने मान लिया था कि उनकी अगुआई के बिना भाजपा का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते भी सहज नहीं रह गए थे। लेकिन जब राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भाजपा जीत गई, तो उन्होंने अपने खबरे के नेताओं की लामबंदी शुरू कर दबाव बनाने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री पद पर एकमात्र हक उनका ही है। लेकिन भाजपा ने भजन लाल शर्मा को आगे कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि खेमेबंदी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का खेमा भी यही मानता था कि उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अपने पुराने कार्यकाल के दागों से मुक्त नहीं थे, इसलिए उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। बता दें कि भाजपा इन तीनों राज्यों में सिर्फ कमान चुनाव ल्चने को ही चेहरा बनाया था न कि किसी सीएम के चेहरे को। मध्यप्रदेश में जरूर भाजपा की सरकार थी, मगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। इस तरह पहले से तय था कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। नए चेहरे को आगे करने का फायदा यह भी मिलाता है कि पहले के नेतृत्व के साथ जो कुछ अनियमितताएं, खराब नीतियां और फैसले जुड़े होते हैं, वे सब हाशिये पर चले जाते हैं। नए चेहरे से नई उम्मीदें बंध जाती हैं। पुराने दाग-धब्बे धुंधले पड़ जाते हैं। उत्तराखंड और गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा ने इसका लाभ उठाया भी है। फिर सबसे बड़ी बात कि इस तरह भाजपा दूसरे राजनीतिक दलों से खुद को अलग खड़ी करती है कि उसमें किसी भी नेता को नेतृत्व सौंपा जा सकता है, वरिष्ठता, लोकप्रियता या पार्टी नेताओं में पकड़ का पैमाना पुरानी बातें हो चुकी हैं। ये नये दौर का भारत है, इसमें सबकुछ नया ही होना है।

कश्मीर का भविष्य उज्जवल

पंकज गाँधी

कश्मीर में थारा ३७० और ३५4 की प्रासंगिकता को ख़त्म करने हेतु देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय गृहमंत्री अमित शाह एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। कश्मीर के जो हालात थे, उस पर एक कहानी याद आती है। एक संयुक्त परिवार में एक ने बनावत कर दी है, कारण यह नहीं है कि वह अपने होशो हवास से अलगा होना चाहता है, उसके पीछे उसके परिवार का दुश्मन, जो उसका पड़ोसी है उसकी सांजिश्न है. वह उस बेटे को बाप से लड़ने के लिए हथियार भी सप्लाई कर रहा है । ऐसे में परिवार के मुखिया की समझदारी किसमे है? वह पड़ोसी के जाल में खुद आ जाये या उस पड़ोसी के जाल से खुद और अपने बेटे को पहले बचाये ? वाजिब है पहला धर्म बेटे को पड़ोसी के चंगुल से बचाना है जो उसके मलिकाप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है. ऐसे मौकों पर मैं कश्मीर के युवाओं से कुछ संवाद करना चाहता हूँ. आप कश्मीरी किसे आजादी कहते हैं? आप भारत संघ में आजाद ही तो हैं और आपके विकास के लिए तो सबसे महफूज भारत संघ में होना ही है. भारत जैसा संघीय देश विभिन्न संसाधनों वाला देश है जिसके संसाधन विभिन्न प्रदेशों में फैले हैं और लोग बिना बीजा पासपोर्ट के आते जाते हैं, माल और सेवाएँ आयात निर्यात की जटिलताओं से मुक्त है और राज्यों ने संसाधनों के संदर्भ मे एक दूसरे के पूरक हो के सिर्फ अपने राज्य और राज्य के लोगों का ही विकास नहीं किया बल्कि अपने राज्य के नागरिको को पूरे भारत के राज्यों मे बिना बीजा पासपोर्ट के रोजगार के अवसर प्रदान किया।

तकनीकी दृष्टि से भारत का हर राज्य अपने आप मे भारतीय संघ का एक देश है। वे अपनी विदेश नीति, संघार नीति और रक्षा नीति संघीय सरकार के पास रह बाकी कार्य खुद से करती हैं, अपवादकाल

बहस तो भाजपा के भविष्य को लेकर होना चाहिए ?



श्रवण गर्ग

हिन्दी भाषी तीन राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त देने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री के ‘मार्गदर्शन’ में जिस तरह मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियों की गईं और स्थापित पार्टी-नेताओं को निस्तेज साबित कर हाशियों पटका गया, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के लिए गंभीर चेतावनी है। विपक्षी गठबंधन की छह दिसंबर की बैठक का कुछ नेताओं द्वारा कथित तौर पर ‘बहिष्कार’ करने की खबरों के बाद से कुछ राजनीतिक समीक्षक चिंता जाहिर करने लगे थे कि एकता के प्रयासों में दरार पड़ गई है। कांग्रेस की पराजय पर हो रही आलोचना में दो तरह की अटकलें तलाशी जा सकती हैं : पहली यह कि तीन दिसंबर के नतीजों के बाद से मोदी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। दूसरी यह कि प्रधानमंत्री द्वारा करार दिया गया ‘धर्मइंडिया गठबंधन’ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।‘इंडिया’ गठबंधन को अग्रिम श्रद्धांजलि देने को उत्सुक आलोचकों का समूह इसके लिए राहुल गांधी की बलि लेना चाहता है।आलोचकों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ऐतिहासिक ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल की शान में क़सीदे पढ़ रहे थे और कर्नाटक जीत में देशव्यापी परिवर्तन की सूनामी ढूँढ़ रहे थे। दो साल पहले पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में तृणमूल की विजय के बाद पंजाब में ‘आप’ और हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेसकी जीत पर आलोचकों

के बीच सुगुवाहट भी नहीं हुई कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को किसी संकट का सामना भी करना पड़ सकता है।हकीकत यह है कि 2014 और 2019 की तुलना में न सिर्फ़ एनडीए कमज़ोर ही हुआ है, इस बात का अनुमान लगाना भी कठिन हो रहा है कि सत्ता में वापसी के लिए भाजपा 272 सीटों के बहुमत का आँकड़ा किन राज्यों से जुटाने वाली है ? आश्चर्यजनक रूप से 2024 के लिए भाजपा का नारा तो यह है कि ‘अब की बार 400 पार’। ऐसा है तो फिर उसके 2029 के लिए नारे की कल्पना भी अभी से की जा सकती है !

सवाल यह है कि भाजपा को 2019 में मिली 303 सीटों में शामिल महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक से प्राप्त 65 सीटों का सहारा क्या क़ायम रहेगा ? भाजपा ने पिछला चुनाव उद्भव की शिव सेना और नीतीश के जद(यू) के साथ लड़ा था। वर्तमान में दोनों साथ नहीं हैं। कर्नाटक में अब सरकार कांग्रेस की है। महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में 2019 की अपनी 18 सीटों में से कितनी बचा पाएगी ? उसकी तेलंगाना की चार ,हिमाचल की चार और झारखंड की ग्यारह सीटों का भविष्य क्या होगा जहां अब विपक्ष की सरकारें हैं ? जिन तीन राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़) में भाजपा की हाल में जीत हुई है वहाँ की 65 में से 61 सीटें तो उसके पास पहले से है। विधानसभा परिणामों से आहत कांग्रेस क्या उनमें कोई दो साल पहले पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में तृणमूल की विजय के बाद पंजाब में ‘आप’ और हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेसकी जीत पर आलोचकों



और संसद से इस्तीफ़े क्यों करवाए गए ? इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों है कि केंद्रीय मंत्री और संसद विधानसभा चुनाव हार गए ? पूरे देश ने देखा कि तीन दिसंबर को नतीजे प्राप्त हो जाने के सात दिन बाद पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा दस दिसंबर को छत्तीसगढ़ के लिए की गई। कोई तो कारण रहा होगा ?

प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आता है कि भाजपा राज्यों के स्थापित क्षत्रपों ने पार्टी आलाक़मान की सत्ता को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया है। 11 दिसंबर को नध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम की नाटकीय अन्दाज़ में घोषणा के पहले और बाद में भी शिवराज सिंह भोपाल में और उसके अगले दिन जयपुर में वसुंधरा राजे जिस अन्दाज़ में पेश आई उसमें आने वाले दिनों की टोह ली जा सकती है। छुपी बात नहीं कि जिस एक व्यक्ति को मध्यप्रदेश में भाजपा की जीत का श्रेय जाता है उसकी न सिर्फ़ चुनाव प्रचार के दौरान घोरा उपेक्षा की गई, उसके उत्तराधिकारी के चयन में भी दूरी और गोपनीयता बनाकर रखी गई। शिवराज प्रतीक्षा करते रह गए होंगे कि कम से कम

एक बुलावा तो दिल्ली से आएगा ! ऐसा तो कुछ नहीं हुआ बल्कि उनके मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। अब लाड़ली बहनें शिवराज सिंह से लिफ्ट-फ्लिटरक विलाप कर रही हैं : ‘हमने तो आपको चुना है !’ उन्हें कौन जवाब देगा ? मोहन यादव तो नहीं ही दे पाएँगे ! पार्टी शायद मानकर चल रही है कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे आदि नेताओं का राज्यों में काम पूरा हो गया है और उनकी ज़रूरत नहीं बची है ! केवल प्रधानमंत्री के तल्लिसम के दम पर ही पार्टी लोकसभा में बहुमत का आँकड़ा पार करना चाहती है ! वे तमाम आलोचक जो इंडिया गठबंधन में मतभेदों की दरारें तलाश रहे हैं इस सचाई की तह में भी जा सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री का जादुई तिल्लिसम अब कमज़ोर पड़ने लगा है ? क्या मतदाताओं ने उनके कहे को नज़रअंदाज़ करना प्रारंभ कर दिया है ? इसका संकेत प्रधानमंत्री द्वारा बाड़मेर के बायतु में दिए गए चुनावी भाषण से प्राप्त परिणामों में तलाशा जा सकता है ! बायतु के अपने बहुचर्चित भाषण में मोदी ने मतदाताओं का आह्वान किया था कि वे कमल के बटन को ऐसे दबाएँ जैसे (कांग्रेस को) फाँसी दे रहे हों। इशारा साफ़ था। परिणामों में क्या हुआ ? भाजपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। बायतु में जीत कांग्रेस की हुई। ऐसे ही नतीजे राजस्थान के तारानगर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, सूरगढ़, झुंझू, आदि स्थानों की सभाओं के बाद निकले। हनुमानगढ़ में निर्दलीय की और बाक़ी सभी जगह कांग्रेस की जीत हुई।

इंडिया गठबंधन में पड़ी कथित दरारों का संबंध भाजपा से मुक़ाबले को लेकर नहीं बल्कि सीटों के सम्मानजनक बँटवारे से है। न ही कोई दल गठबंधन को छोड़कर गया है। पूछा जा सकता है कि तीन महत्वपूर्ण राज्यों में इतनी बड़ी जीत के बाद एनडीए के साथ कितने दल और जुड़ गए ? कोई भी क्यों नहीं जुड़ा ? मध्यप्रदेश और राजस्थान में पहले टिकिटों के बंटवारे फिर मुख्यमंत्री-चयन को लेकर जो अंदरूनी संघर्ष प्रकट हुआ उसे अगर नज़रअंदाज़ नहीं करना हो तो असली बहस तो भाजपा और एनडीए के भविष्य को लेकर होना चाहिए ! शिवराज सिंह ने तो भोपाल में संकेत दे दिये हैं : ‘मर जाऊँगा पर काम माँगने दिल्ली नहीं जाएगा।’ देखना यह है कि भजनलाल शर्मा द्वारा शपथ ले लेने के बाद वसुंधरा राजे जयपुर में क्या करने वाली हैं ? लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के पास भी ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है !

http://shravangarg1717.bl ogspot.com

मोहन यादव के बहाने चुनाव साधने की कवायद



अशोक भाटिया

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मोहन यादव को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पर असर पड़ सकता है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में। यही नहीं, एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने राहुल गांधी के ओबीसी दांव की काट करने की कोशिश की है। मायने साफ है कि आप तो सिर्फ कह ही रहे हो जबकि वास्तव तो बना ही दिया है। आप तो ओबीसी अफसरों की गिनती ही कर रहे हैं. हमने तो एक बड़े राज्य में मुख्यमंत्री ही इस तबके का बना दिया। इसके लिए पुराने और बड़े चेहरों को भी दरकिनार किया है। यह सब गिनवाया जाएगा। आगे जब बाकी राज्यों में जाति सर्वे की मांग उठेगी तो भाजपा इन ओबीसी चेहरों को उस मांग के सामने खड़ा करेगी। एक तरह से यह चेहरे ही पार्टी के लिए सेफ्टी वॉल का काम करेंगे। ऐन लोकसभा चुनाव के मुहाने पर इस काट के मान्ये बड़े हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हिन्दी बेल्ट में ओबीसी की सबसे बड़ी जातियों में से एक यादवों को पाले में लाने के लिए मोहन यादव का चयन मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सिर्फ मप्र की ही बात करें तो यहां ओबीसी आबादी 51% है। इस तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पिछड़ा वर्ग समाज से आता हो। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और राजद पर परिवार भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती है तो वहीं अब मध्यप्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि अब वह उत्तरप्रदेश और बिहार के यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने को तैयार है। भाजपा यह मानती है कि राजद और जदयू के एक साथ होने के बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी चुनौती बिहार में मिल सकती है, इसलिए भाजपा हर वह दांव चल रही है जिससे विरोधियों को बैकफुट पर रखा जा सके। मध्यप्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाएं जाने पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह मानना है कि भाजपा जाति की नहीं, जमात की राजनीति करती है। भाजपा पहले से ही

कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का निर्णय भी इसी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राजद बनने के बाद से लालू प्रसाद यादव ही राजद के अध्यक्ष रहे। जब मौका मिला तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और फिर बेटी और बेटे को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या बिहार में कोई अन्य यादव नहीं है। जाति किसी की जागीर नहीं है। यहां आपको यह भी बता दें कि हाल ही में बिहार में हुई जिनगीन जगणाना के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहां कुल आबादी में से 14. 26 प्रतिशत आबादी यादवों की है। राजद ने मुस्लिम-यादव वोट बैंक के दम पर ही बिहार में 15 सालों तक सरकार चलाया था। ऐसे में मध्यप्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाने के बाद यह माना जा रहा है कि इसका सीधा असर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि यादव ना सिर्फ उत्तरप्रदेश - बिहार बल्कि हरियाणा, मप्र में भी बड़ा संख्या में हैं। सिर्फ बिहार-उत्तरप्रदेश में ही लोकसभा की 120 सीटें हैं। यदि मप्र और हरियाणा को भी जोड़ लें तो सीटों की संख्या 159 तक पहुंच जाती है। पिछली बार यहां भाजपा उस वर्ग की सीधे तौर पर प्रभावित और प्रेरित करने का प्रयास नहीं किया की तरफ से किया गया है। दोनों राज्यों में करीब 10 से 12 प्रतिशत की आबादी यादव की है। मोहन के साथ जुड़े यादव से अगर उस वोट बैंक का कुछ हिस्सा भी पार्टी की तरफ आ गया तो लोकसभा में खेल बदल सकता है। भाजपा ने मोहन यादव के नए मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही मप्र में लालकृष्ण आडवाणी के युग के क्षत्रपों की जगह मोदी ने भाजपा की नई लीडरशिप गढ़ने की कवायद भी शुरू कर दी है। इससे साफ है कि अब नई भाजपा 2. 0 दिखाई नए नेता सामने आएंगे। नाम चमकाने के प्रयासों की जगह साइलेंटली किए जा रहे हैं. काम को महत्व मिलेगा। यह प्रयास असर राज्यों में भी दिखाई देंगे। युवाओं को महत्व मिलेगा। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव लंबे समय से आरएसएस के करीबी रहे हैं हालांकि उन्होंने अपनी तरफ पर एबीवीपी से शुरू की थी। बाद में वे आरएसएस की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। मालवा, विशेष रूप में उज्जैन में उन्होंने संघ में काफी काम किया है। मालवा हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। 2013 के विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो हर चुनाव में उसे इस क्षेत्र से

बेहतर रिसॉस मिलता है। मालवा क्षेत्र से मुख्यमंत्री मिलाना आगे के चुनावों में लोगों को जोड़ने के नजरिये से बहुत काम आएगा। यहां लोकसभा की आठ सीटें हैं जिन पर भाजपा ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। भाजपा लोकसभा चुनावों में भी अपने परंपरागत गढ़ को बचाए और बनाए रखना चाहती है। यहां से मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा के रूप में एक डिप्टी मुख्यमंत्री चुनकर क्षेत्र को उसकी लॉयल्टी का एक तरह से तोहफा मिला है। ऐसा नहीं है कि मप्र में सिर्फ ओबीसी वर्ग को ही महत्व दिया गया है। यहां दो डिप्टी मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य वर्गों को साधने की कवायद से भी अपने परंपरागत गढ़ को बचाए और जगदीश देवड़ा को डिप्टी बनाकर ब्राह्मण और एससी वर्ग, वहीं नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर राजपूतों को साधने का प्रयास किया गया है। जानकार लोगों के अनुसार उत्तरप्रदेश में सपा का यह सबसे ठोस वोट बैंक हैं। लोकसभा में इस समय चार यादव सांसद हैं जिसमें दो सपा, एक बसपा व एक भाजपा का है।दूसरी ओर, बिहार में आए हालिया जातीय सर्वे के अनुसार वहां यादवों की जनसंख्या 14. 30 फीसदी है। यहां से पांच यादव लोकसभा पहुंचे हैं, जिसमें नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है हालांकि यादव यहां लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। आरजेडी- जेडीयू की प्रदेश सरकार में 25 फीसदी मंत्री इसी विरादरी से हैं। ये आंकड़े इन राज्यों की सियासत में यादव वोटरों के दम की तस्वीर पेश करते हैं।मध्यप्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी इसी दौर का हिस्सा माना जा रहा है।बिहार में 2013 में यादव चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर सरकार-संगठन तक भागीदारी बढ़ाई गई। लालू के खास रामकृपाल यादव जैसे चेहरे साथ लाए गए,वहीं, उत्तरप्रदेश में गिराीश यादव मंत्री हैं। मुलायम परिवार के करीबी माने जाने वाले चेहरों तक को भाजपा अपने पाले में करने में सफल रही है। यहां तक कि दोबारा सपा में लौटे मुलायम के भाई शिवपाल यादव भी मैमपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के पहले भाजपा व सरकार के ही नजदीक खड़े थे।

राज सक्सेना

नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से उठ रही है। एक विशाल आंदोलन के बाद 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करने वाले लोग तर्क देते हैं कि नेपाल एक हिंदू बहुल देश है और इसलिए इसे एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता ने नेपाल के हिंदू मूल्यों और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। हिंदू राष्ट्र की मांग के समर्थन में कई आंदोलन हुए हैं। 2023 से नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, कई हिंदू संगठनों ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रबल समर्थन दिया है। हिंदूराष्ट्र की मांग, नेपाल की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। यह देखना बाकी है कि क्या नेपाल सरकार निर्यादों को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है हालांकि यादव यहां लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। आरजेडी- जेडीयू की प्रदेश सरकार में 25 फीसदी मंत्री इसी विरादरी से हैं। ये आंकड़े इन राज्यों की सियासत में यादव वोटरों के दम की तस्वीर पेश करते हैं।मध्यप्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी इसी दौर का हिस्सा माना जा रहा है।बिहार में 2013 में यादव चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर सरकार-संगठन तक भागीदारी बढ़ाई गई। लालू के खास रामकृपाल यादव जैसे चेहरे साथ लाए गए,वहीं, उत्तरप्रदेश में गिराीश यादव मंत्री हैं। मुलायम परिवार के करीबी माने जाने वाले चेहरों तक को भाजपा अपने पाले में करने में सफल रही है। यहां तक कि दोबारा सपा में लौटे मुलायम के भाई शिवपाल यादव भी मैमपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के पहले भाजपा व सरकार के ही नजदीक खड़े थे।

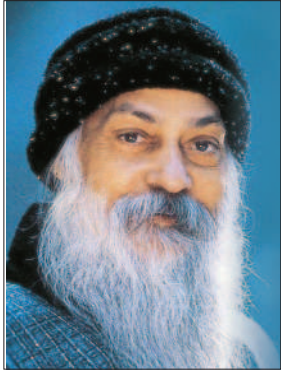
राजनीतिक व्यवस्था को व्यापक रूप से निष्क्रिय माना जाता है और इसे देश के राजनेताओं के हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया माना जाता है।

नेपाल भीषण बेरोजगारी से घिरा हुआ है। दौड़ती मुद्रास्फीति ने गंभीर वित्तीय संकट और खराब प्रशासन के साथ-साथ सिस्टम के खिलाफ जनता में गुस्सा पैदा कर दिया है। देश की आर्थिक स्थिति काठमांडू घाटी के बाहर, समुचित भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी, खराब स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल और शिक्षा सुविधा के अतिरिक्त एक अल्प विकसित सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क से जुड़ा रहा वातावरण, लोगों का वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में तेजी से विश्वास खो रहा है।

पूरे देश में लाखों लोगों से उनकी मेहनत की कमाई को उन सहकारी समितियों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा लूट लिया गया है जिनके संरक्षक शक्तिशाली राजनेता हैं। इससे भी गुस्से की लहर पैदा हो गई है। अंधकार में भविष्य को जाते देख, नेपाल की क्रांति और अस्तित्व जनता ने यह मानना शुरू कर दिया है कि एक संवैधानिक राजशाही देश के लिए सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली होगी। देश की विशाल हिंदू आबादी राजा को भावनात्मक विष्णु के जीवित अवतार के रूप में देखती है। 2008 में देश के धर्मनिरपेक्ष हो जाने को लेकर हिंदुओं के बड़े वर्ग में नाराजी बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र की स्थिति में इस वक्त बदलाव ने ईसाई और मुस्लिम प्रचारकों के लिए दरवाजे खोल दिए। जिन्होंने देश में लोगों का फायदा उठाकर कई गरीबों को ईसाई धर्म में प्रत्यावर्तित कर दिया और प्रलेपन के माध्यम से इस्लाम में प्रत्यावर्तन सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है। नए धर्माति लोग हिंदू पूजा स्थलों पर भी हमले कर रहे हैं। इसलिए नेपाल को एक बार फिर हिंदूराष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है।

प्रचंड के सीपीएम यूएमएल प्रमुख ओली के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे लेकिन दोनों के बीच अनबन हो गई। एक साल पहले से प्रचंड न केवल ओली बल्कि वर्तमान शासन प्रणाली के भी कटु आलोचक बन गए हैं। प्रचंड ने ओली के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने ओली पर भारी संपत्ति अर्जित करने और गलत तरीके से अर्जित धन को कंबोडिया में संपत्तियों और उद्योगों में निवेश करने का आरोप लगाये हैं। प्रचंड को एहसास हुआ है कि लोग राजनेताओं की वर्तमान पीढ़ी से नाराज थे और शासन की वर्तमान प्रणाली परिणाम देने में विफल रही है। प्रसेन ने इस आम गुस्से का फायदा उठाया और अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे आंदोलन शुरू किये।





दरअसल, ओशो को चाहने वाले आज भी उन्हें इसी तरह याद भी कर रहे हैं जैसे वे कहीं गए ही नहीं। ये कांम सोशल मिडिया और आसान किए देता है कि ढेरों वीडियो देखे जा सकते हैं। उन वीडियो में जो बातें वे कर रहे हैं, वे युवाओं को बड़ी भाति हैं। उनकें बागी मन को, जब नई-नई समझ पकड़ता मन दुनिया को बदलने को, रूढ़ियों को तोड़ने की चाह रखता है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ युवा मन ही, दबे-दबे ही सही समाजिक लोग भी ओशो की हैं। में हां ही मिलाना चाहते हैं। समाजिक इसलिए लिखा है कि ओशो समाज के लिए नहीं थे, इसलिए कई जगह से बेदेखल भी किए गए पर सन रहे कि शरीर से बेदेखल कर देना विचार से

देखल कर देना तो नहीं है तो उनके लोग उनसे प्रभावित हुए उनसे लिए वे प्रिय हैं, उन पर किताबें लिखी जा रही हैं, चर्चाएँ की जा रही हैं, उनके बनाए सैन्टर में डायनामिक मेडिटेशन भी किया जा रहा है।

मोरारी बापू से लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री और सदरु तक भी सभी ने ओशो की तारीफ़ के पुल बांधे हैं। ओशो की नक़्क़ारना मुश्किल है, हाँ द्वेष और प्रेम निजी मसला है, ये बात तो वे खुद भी कहते थे।

ओशो का कहा सब कुछ वीडियो के रूप में तो दर्ज नहीं है लेकिन सौभाग्य से इतना है कि उन्हें समझा और जाना जा सके। आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश बनने के बाद वो उनके फॉलोअर्स के लिए ओशो हो गए थे। ओशो का मतलब विराट समुद्र से एक हो जाना, दार्शनिक भाषा में इसका अर्थ है ईश्वर से हैं। अर्थात् इश्वर से एकता ही अवस्था। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ओशो एनलाइटेंड थे जिस ज़रूरत पर उन्होंने कहा कि और अदृश्य का अनुभव आप स्वयं न करे लें वह दूसरों के माध्यम से कैसे जानेंगे। अध्यात्म वह एक अनुभव देता है, वह एक अनुभूति। ओशो का कहा

रखलियाँ और खींचता है कि उनके पास एक तार्किक दिमाग था और तीव्र मेधा। गोपालदास नीरज, विनोद खन्ना, अमिता प्रीतम, सुश्रवात सिंह, सुमित्रानन्दन पंत उनसे मिलने आश्रम पहुँचे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पकड़ रखने वाले जब ओशो मेरे प्रिय आत्मन से शुरू करते और अंदर बड़े परमात्मा को प्रणाम कर अपनी बात समाप्त करते। हजारों और फिर लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आने लगी। बंबई में दो कमरों से मकान से शुरू हुआ सफ़र पुणे की बड़ी बड़ी ज़मीन से होता हुआ अमेरिका पहुँचा। भावान रजनीश का कम्यून जो उनके विचारों और सपनों का समाज था, उसका पूंजीवादी विस्तार हुआ। रोलस रॉयस गाड़ियों से लेकर, महंगी घड़ी, ज़्वैचरों और कपड़ों तक। बंबई की सेक्रेटरी लक्ष्मी का पद आन शिला को मिल गया। सन्यास के बाद जिसका नाम हुआ माँ आनंद शिला। वे एक अच्छी ठाँव हैं, ये शिला के शब्दों की बात है। यद्य ओशो के प्रेम में थीं और ओशो भी उनके प्रेम में थे, उन्होंने दावा किया हालाँकि किसी भी शारीरिक संबंध की बात से इंकार किया। (जारी)

वरना झेलनी पड़ सकती है बड़ी मुसीबत

गड़ख पुराण में जीवन के जन्म और मृत्यु के अटल सत्य को बताया गया है। इस पुराण में नरक लोक की यातनाओं और उनसे बचने के बारे में भी बातें लिखी हुई हैं। यदि पुरुषों में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो उसकी शांति के लिए ये एक पूजा करना चाहिए जरूरी होता है। आदर जानते हैं आखिर वो कौन सी पूजा है।

हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण अवस्था तक कामकांड का विधान है। बात करें पुराणों में तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ का दिव्य संवाद है। पंथराज



इच्छाएं, परिवार से मोह और अपने-से उम्मीदें ये सभी बातें उस समय जीवात्मा को घोर पीड़ा देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह जीवात्मा अपनी सीमित आयु की अवधि तक 84 योनिओं में से प्रेत योनि को प्राप्त करती है और जब तक पूर्ण आयु अवधि नहीं पूरी होती है। वह इधर-उधर भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकती रहती है। यह सब कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है।

अकाल मृत्यु हो जाने पर कराएं नारायण बलि पूजा

जीवात्मा को जब शांति नहीं मिलती या उसके निमित्त उचित क्रिया कर्म और अंतिम संस्कार नहीं होता तो वह अपने परजनों से यह अपेक्षा करती है कि वह उसके निमित्त उचित कर्माकांड करा कर उसे मुक्ति दिला दें। जब तक जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती वह पितृ रूप में प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्युलोक में भरुड़की रहती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान बताया गया है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद नारायण बलि ही एक ऐसी पूजा है जिसे विधि विधान द्वारा कराने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाती है। विष्णु जी से की जाती है मुक्ति

की प्रार्थना गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि की पूजा में भगवान विष्णु से जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके कर्मों के प्राश्निक के लिए छमा याचना की जाती है। इस पूजा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के निमित्त एक-एक पिंड बनाया जाता है।

यह पूजा 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है। इस पूजा में विधि पूर्वक पिंडों दान समेत जीवात्मा की मुक्ति के लिए पूजा पद्धति अपनाई जाती है। यह पूजा कराने से आकाश मृत्यु प्राप्त जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और परिजन पूति रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह पूर्वज रूप में सदैव के लिए उस घर में संपन्नता का आशीर्वाद बना देते हैं। जो लोग आकाश मृत्यु होने पर परिजनों के निमित्त यह पूजा कराते हैं उनके ऊपर पितृ दोष नहीं लगता है।

तीर्थ स्थल में करा सकते हैं नारायण बलि की पूजा

गरुड़ पुराण के अनुसार इस पूजा को पवित्र तीर्थस्थल, देवालय या तीर्थजल और घाट के पास कराना बेहद फलदायक होता है। यह पूजा पितृ पक्ष या फिर किसी बड़ी अमावस्या के दिन ही करानी चाहिए।

मंदिर
में पूजा का समय सुबह
6.30 बजे से आरंभ होता है।
दोपहर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है।
फिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात
के 9 बजे बंद हो जाता है। शुक्रवार से
रविवार तक मंदिर दोपहर 1 बजे
तक खुला रहता है।



शास्त्रों में लिखा गया है कि देवतों से ज्यादा शक्तिशाली माता रानी को बताया गया है। हर शख्स अपने जीवन में धन, विद्या, वैभव और शक्ति के लिए माता रानी की आराधना करता है। आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताया जा रहा है।

चेन्नई के अडयार समुद्र तट पर अष्टलक्ष्मी का सुंदर मंदिर स्थित है। अष्टलक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी माता के आठ रूपों को समर्पित है। देवी लक्ष्मी के ये विविध रूप हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

अष्टलक्ष्मी में धन, विद्या, वैभव, शक्ति और सुख प्रदान करती हैं। इस मंदिर में लक्ष्मी की आठ अलग-अलग

मूर्तियां अलग-अलग तलों पर स्थापित की गई हैं। यहां आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, संतना लक्ष्मी और धन लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। सभी देवियों के मंदिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सबसे अंत में नवम मंदिर है, जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का है। इस मंदिर में विष्णु की तुलना में लक्ष्मी को प्राथमिकता दी गई है।

इस मंदिर का निर्माण 1974 में आरंभ किया गया। मुकुट श्रीनिवास वरदचैरियार की अगुवाई में बनी समिति ने इस मंदिर का निर्माण कराया। 5 अप्रैल 1976 से इस मंदिर

में विधिवत पूजा आरंभ हुई। मंदिर का डिजाइन ओम के आकार का है। नवरात्रि और गोकुलाष्टमी मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कमल का पुष्प जरूर चढ़ाते हैं।
हर लक्ष्मी के लिए लोग अलग-अलग कमल के फूल लेकर जाते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से से समुद्र का सुंदर नजारा दिखाई देता है।
वहीं समुद्र के तट से मंदिर भी काफी सुंदर नजर आता है। मंदिर का निर्माण तीन मंजिलों में हुआ है। मंदिर के चारों तरफ विशाल आंगन है। इसके परिसर में पूजा सामग्री की दुकान भी है।

महालक्ष्मी का वास्तुशास्त्र से भी अनूठा रिश्ता है। जहाँ उत्तर और पूर्व हल्का व खुला हुआ, प्रकाशमान हो, जल युक्त, अग्निविहीन, नीचा, चमकदार और बड़ा हुआ, उत्तर पूर्व में भारी समान न हो, दक्षिण पूर्व यानि आग्नेय में अग्नि, चूल्हा या बिजली से चलने वाली मशीनें हों, दक्षिण पश्चिम कोण बंद, उत्तर और भारी हो, वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा जहाँ बैठने की व्यवस्था उत्तर या पूर्वमुखी हो, खाना-पूर्वाभिमुख होकर बनाया जाता हो, मालिक दक्षिण-पश्चिम कोने में वास करता हो, लोग दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हों वहाँ लक्ष्मी सुख-समृद्धि के रूप में होती हैं। जहाँ परनिंदा न हो और अतिथि, संतों, बुजुर्गों का सम्मान हो, परिजन तीखे चपन न बोले, घर में घंटियाँ बजती हों, वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर वास करती हैं।

कर्ज कब लें, कब नहीं
मान्यताओं के अनुसार मंगलवार, हस्त नक्षत्र के साथ रविवार, संक्रांति या वृद्धि योग हो तो ऋण काटने में लें, अन्यथा कर्ज के भयसागर में अकंटक डूब जाएंगे। मंगलवार को उधार लिया गया धन वापस हो जाता है, उसे लौटा पाना असंभव सा हो जाता है। यदि ऋण चुकाना हो, तो मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आमवासा, व्यतिपाद्य, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराषाढा नक्षत्र, भद्रा तथा पुष्य के दिन किसी को उधार न दें। इस दिन उधार लिया हुआ धन वापस नहीं लौटता। या तो डूब जाता है, या विवाद का पायब बन जाता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि चक्र की नववीं राशि धनु के लोग बेहद खास होते हैं। इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इनकी कुछ विशेषताएँ दूसरी राशि के लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं, जिनको देखकर आप अपने प्रियजनों का स्वभाव भी जान सकते हैं।

धनु राशि के लोग ईमानदार, सच्चे, विश्वास योग्य और समझदार होते हैं। हालाँकि इनमें काफी अधिक गुस्सा भी पाया जाता है और काफी-कभी आक्रामक हो जाते हैं। अध्यापन और दर्शन में करियर बनाएँ तो बहुत सफल होते हैं।

भारतीय ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु होती है, प्रायः वे लोग प्रेम जीवन में आजाद छयाल और बड़े दिल वाले होते हैं। आइये जानते हैं धनु राशि वाले कैसे होते हैं।

धार्मिक और बुद्धिमान

ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के लोग

धार्मिक होने के साथ-साथ बुद्धिमान भी होते हैं। प्रायः इनके मन और शरीर में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, इसलिए ये दूसरों की सलाह लेते हैं। साथ ही धनु राशि वाले लोगों का रोमांस की बजाय प्यार के प्रति आकर्षण अधिक होता है। आशावादी और हंसमुख होते हैं धनु राशि के लोग धनु राशि के लोग प्रभावी वक्ता और भविष्य के प्रति आशावादी होते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार धनु लग्न के लोग प्रायः अच्छे और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। इनमें एक बुरी बात यह देखी जाती है कि विपरीत परिस्थितियों में संस्य छोड़ देते हैं और जबाबदेही के प्रति आशंकित रहते हैं। बातचीत में जल्दवाजी



करते हैं, जिसके कारण कई बार दूसरे लोग इनको गलत समझ लेते हैं। कभी-कभी भ्रम के प्रति इनमें रुझान होता है।

महत्वाकांक्षी और खर्चीले

धनु लग्न वाले लोग प्रायः आशावादी, महत्वाकांक्षी, प्रेरणादायक, उत्साही और

खचीले होते हैं। इनका जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक, ऊर्जा से ओझड़ित, साहसी, अपने अनाभव को दूसरों से अधिक से अधिक बॉटने वाला होता है। अनावश्यक बातों से दूसरों को लुभाने में रुचि नहीं होती। आप लोग यात्रा करना पसंद करते हैं और आसपास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी पसंद करते हैं।

खूब मिलती है प्रतिष्ठा

धनु लग्न वालों को खूब मान प्रतिष्ठा मिलती है। इस लग्न के लोग सम्मानित, ईमानदार, विश्वासी, उदार और न्याय के प्रति वफादार होते हैं।

आप आम तौर पर फैशन की चाह रखने वाले और ईमानदारी की मजबूत भावना के साथ आध्यात्म की ओर झुकाव रखने वाले होते हैं। धनु लग्न के लोग मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं और वे किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम देने का हर यत्न करते हैं।

आर्टिकल 370 हटाने के रास्ते में तीन सबसे बड़े कटि थे

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एक्सक्लूसिव डेस्क)। 26 वकील, 23 याचिकाएं, 16 दिन और 5 जस्टिस। इस मैराथन बहस के बाद 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- ‘हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं।’ सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राष्ट्रपति के सभी कदमों पर मुहर लगा दी। ये साफ संकेत हैं कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वक्त तमाम अड़चनों को हटाकर किनारी पुख्ता कानूनी तैयारी की गई थी। आखिर वो तीन कदम क्या थे, जिन्हें आर्टिकल 370 हटाने से पहले गृहमंत्री शाह ने उठाए थे

पहला कदम: आर्टिकल 370 में ‘संविधान सभा’ की जगह विधानसभा शब्द शामिल किया। 5 अगस्त 2019 को उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सीओ 272 जारी किया। इसके जरिए केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 367 में बदलाव किया। अनुच्छेद 367 में संविधान को पढ़ने यानी उसमें शामिल शब्दों की व्याख्या दी गई है। यह

गृहमंत्री ने उन्हें कैसे निकाला कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी को वैध बताया

बदलाव ऐसा था कि अनुच्छेद 370 (3) में शामिल शब्द ‘संविधान सभा’ की जगह ‘विधानसभा’ शब्द शामिल किया गया। जम्मू-कश्मीर भारत का अकेला ऐसा राज्य था, जिसका अपना अलग संविधान और उसे लिखने वाली संविधान सभा थी। भारत में विलय के बाद शुरुआती सालों में अनुच्छेद 370 में कोई भी बदलाव राज्य की संविधान सभा की सलाह पर ही हो सकता था। कुछ सालों बाद संविधान सभा में शामिल सभी सदस्य दुनिया में नहीं रहे, ऐसे में अनुच्छेद 370 में बदलाव एक कानूनी पेच बन गया था। अब राष्ट्रपति के इस आदेश के जरिए संविधान सभा की यह शक्ति जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को दे दी गई। ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति के आदेश के जरिए केंद्र सरकार ने यह बदलाव अनुच्छेद 370 (1) में दी गई शक्तियों के दम पर ही किया।

विधानसभा भंग थी, इसलिए संसद ने रखा वैधानिक प्रस्ताव संविधान सभा का कानूनी पेंच निकल चुका था। इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

ने राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव रखा। कुछ ही देर में राज्यसभा ने अनुच्छेद 370 को हटाने का यह प्रस्ताव पारित कर दिया। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसे में जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सभी शक्तियां भारत की संसद में आ गईं। मतलब यह कि केंद्र सरकार ने 370 को हटाने की राह से पहले जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुमति का पेंच हटाय़ा, फिर विधानसभा की अनुमति यानी प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं पड़ी। यानी जम्मू-कश्मीर विधानसभा के प्रस्ताव की जगह संसद का प्रस्ताव काफी था और हुआ भी यही। 6 अगस्त 2019 को तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदेश सीओ 273 जारी कर राज्यसभा के प्रस्ताव को लागू कर दिया। आखिरकार 370 (1) का इस्तेमाल करके 370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया गया। यानी जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तत्कनीकी तौर पर 370 (1) आज भी बरकरार है।



जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया

अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 राज्यसभा में रखा। 9 अगस्त 2019 को संसद के दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इनमें जम्मू और कश्मीर राज्य में विधानसभा को बरकरार रखा गया। वहीं लद्दाख को पूरी तरह केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।

5 जजों की संविधान पीठ ने 5 अहम बातें कहीं

1. अनुच्छेद 370 अस्थायी है :

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान के चैप्टर-21 का हिस्सा है, जिसका शीर्षक ही अस्थायी प्रावधान है। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, ताकि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा बन जाए और ये भारतीय संविधान को रैक्टिफाई करे। दूसरा, जंग के हालात में इसकी जरूरत महसूस हुई थी। 2. जम्मू-कश्मीर को आंतरिक संप्रभुता नहीं : जम्मू-कश्मीर को आंतरिक संप्रभुता के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने कहा- भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं बची थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के

सेक्शन 3 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। 3. राष्ट्रपति के फैसले की नीयत सही : चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति और संसद राज्यपाल/विधानसभा के रूप में टेक-ओवर कर सकते हैं। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के एक्शन की सीमाएं होती हैं। इस केस में पहली नजर में ये नहीं लगता कि राष्ट्रपति का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया हो या उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो। 4. जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले : इस विषय को सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए खुला रखा है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकार जल्द

ही जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाल करेगी। इसलिए जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम 2019 की वैधानिकता के सभी पहलुओं पर संविधान पीठ ने अभी फैसला नहीं दिया है। 5. राष्ट्रपति के फैसले कानून सम्मत : देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद-370 के तहत आदेश जारी करके जम्मू-कश्मीर में अनेक संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया था। उसके बाद भी संसद से पारित अनेक कानूनों को राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया। राष्ट्रपति के आदेश सीओ- 272 के पैरा 2 के जरिए संविधान के जो प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू किए गए, वे कानून सम्मत हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पुर्नविचार याचिका की सुनवाई फैसला करने वाले बेंच के सामने ही बंद कमरे में होती है। कई बार याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में भी रिव्यू मामलों की सुनवाई होती है। आर्टिकल 370 मामले में

फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ के एक सदस्य जस्टिस कौल दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। इसलिए यदि कोई रिव्यू दायर हुई तो उसकी सुनवाई के लिए नए सदस्य के साथ बेंच का गठन चीफ जस्टिस करेंगे। मुख्य मामले की लिस्टिंग और सुनवाई में कई साल लग गए, ऐसे में रिव्यू की सुनवाई में भी देरी हो सकती है। रिव्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित मामला होता है, इसलिए उसमें याचिकाकर्ताओं को विशेष राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। हालांकि, एक मामले में दो विरोधाभासी फैसले हो तो न्यायिक आदेश से बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है। मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को 7 जजों की बेंच से सुनवाई की मांग करनी चाहिए थी। संविधान पीठ के 5 जजों के विस्तार से फैसले के बाद अब 7 जजों की बेंच गठित होने की संभावना नहीं है। संपूर्ण राज्य को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया जाने के संसद और केंद्र सरकार के अधिकांश के बारे में भविष्य में 7 जजों के संविधान पीठ में सुनवाई हो सकती है।

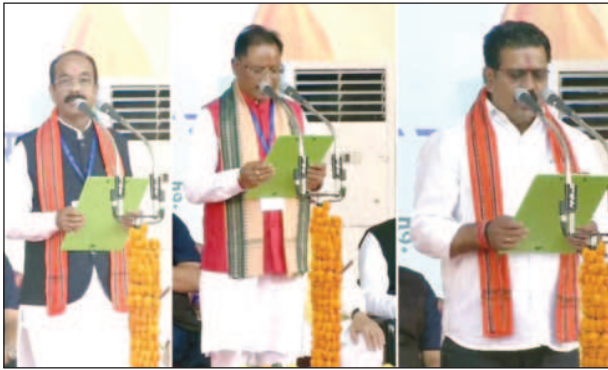
विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री

रायपुर, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। रायपुर में उन्होंने हिंदी में सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद साय मंत्रालय पहुंचे हैं। यहां यहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम स्थल साईंस कॉलेज मैदान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।

साव ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा

सीएम पद की शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान रायपुर

अरुण साव और विजय शर्मा बने डिप्टी सीएम, शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय पहुंचे साय



उत्तर से विधायक पुंरेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुरैना स्थित अपने आवास पर पत्नी के साथ नवग्रह पूजन भी किया। साय ने अपनी मां जसमनी देवी का आशीर्वाद लिया। अपने बेटे की सफलता से भावुक मां ने उन्हें गले लगा लिया। विष्णु देव साय रायपुर के अवंति विहार एटीएम कौक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद जय स्तंभ चौक स्थित

शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा- ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का बहुत-बहुत अभिन्नंदन और आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम मोदी की गारंटी को पूरा करेगी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।’

इस मौके पर ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ‘बदलवो’ का नारा पूरा किया। वहीं पीएम मोदी का स्वागत एक थीम सॉन के साथ किया गया। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे इस थीम सॉन के साथ स्वागत और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ।

प्रधानमंत्री समेत ये दिग्गज रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर

छत्तीसगढ़ सीएम की शपथ से पहले आईईडी ब्लास्ट

जगदलपुर, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ में सीएम के शपथ ग्रहण से ठीक पहले नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में आईईडी ब्लास्ट किया है। आईईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आमदई खदान के पास सीएएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे, उसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। मामला छोटेटोंगर थाना क्षेत्र का है। ब्लास्ट में शहीद जवान कमलेश साहू जांजगीर-चांपा जिले के हसीद गांव का रहने वाला था। पिछले 3 दिन में हुई अलग-अलग घटनाओं में अब तक 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान शहीद हुआ है।

सुरक्षाबलों की ओर से भी जवाबी फायरिंग

बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि नारायणपुर के थाना छोटेटोंगर क्षेत्र के आमदाई खदान में करीब 11 बजे नक्सलियों ने

नारायणपुर में एक जवान शहीद, एक घायल, 3 दिन में अलग-अलग धमाके में 6 जवान जखमी



आईईडी विस्फोट और फायरिंग की। जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी फायरिंग की गई। नक्सलियों के हमले में सीएएफ 9वीं वाहिनी का जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गया। एक आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। आसपास के इलाके में पुलिस बल, डीआरजी

और आईटीबीपी जवान सर्चिंग में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक, आमदई खदान के पास बुधवार सुबह सीएएफ के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। यहां जवानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूवे से नक्सलियों ने पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा हुआ था। इसी बीच सर्चिंग के दौरान एक जवान कमलेश कुमार का पैर नक्सलियों

की लगाई प्रेशर आईईडी पर आ गया, जिससे जोर का धमाका हुआ। इस घटना में कमलेश को गंभीर चोट आई, वे मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके की चपेट में आने से एक अन्य जवान विनय कुमार को भी चोट आई है। साथी जवानों ने दोनों को फौरन मौके से निकाला और छोटेटोंगर के अस्पताल लेकर आए हैं। जहां घायल जवान का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि, इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 24 नवंबर को इसी इलाके में बम फटा था। नक्सलियों की लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर घायल हुआ था। ये सभी मजदूर आमदई माईंस में काम करने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान प्रेशर आईईडी पर इनका पैर आ गया था।

साय कैबिनेट में बिलासपुर संभाग से 7 की दावेदारी मजबूत

अमर या कौशिक को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका

बिलासपुर, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में बिलासपुर संभाग का दबदबा रहने की पूरी संभावना है। अरुण साव अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, तो बिलासपुर से अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक में से एक को ही मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं रायगढ़, कोरबा और मुंगेली जिले से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जांजगीर-चांपा जिले को छोड़ दें, तो हर जगह से कैबिनेट में मंत्री पद के दावेदार

हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बिलासपुर उपेक्षित रहा, क्योंकि यहां पहली बार विधायक बनने वाले शैलेश पांडेय पूरे 5 साल विपक्षी विधायक की भूमिका में रहे, तो वहीं तखतपुर से पहली बार विधायक बनीं रश्मि सिंह को संसदीय सचिव का पद मिला। अब भाजपा की सरकार आते ही दिग्गज नेताओं के चुनाव जीतने पर एक बार फिर से मंत्रिमंडल में बिलासपुर जिले का रुतबा बढ़ेगा।

हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा, अमन हत्याकांड की जांच एसआईटी से कराएंगे

रांची, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। धनबाद जेल में कुख्यात शूटर अमन सिंह की हत्या मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने बताया है कि इस मामले में एसआईटी बनाने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में एसआईटी के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा है। 3 दिसंबर को धनबाद जेल में

अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमन सिंह पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्या मामले में लंबे समय से जेल में बंद था। अब इस मामले में जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में बड़ी साजिश होने की बात कहते हुए राज्य सरकार को एसआईटी जांच कराए जाने से संबंध में जवाब मांगा था। सिख दंगा मामले में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने व क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को दबोचा

गिरिडीह, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। गिरिडीह में एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अलग-अलग थाना से पुलिस ने नौ शांतिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आज की गिरफ्तारी के बाद बीते 100 दिनों में गिरिडीह जिले में 100 साइबर अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 55 मोबाइल फोन, 36 सिमकार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आईपैड, 1 लैपटॉप,

तीन पावर बैंक और चार बाइक बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के तिलकडीह का मनीष कुमार मंडल, बेंगाबाद थाना क्षेत्र का विकास मंडल, बेंगाबाद के सोनबाद का सागर तुरी, गांडेय थाना क्षेत्र के आहारडीह का मो. मुस्ताक अंसारी, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर का सगीर अंसारी, बेंगाबाद के लखनपुर का इनामुल हक, सयुम अंसारी और बुइई थाना क्षेत्र के कुम्हारद्विया का रहने वाला अजरूदीन अंसारी शामिल है।

लोकसभा चुनाव, आंतरिक सर्वे में भाजपा का दावा

रांची, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा के हांसले बुलंद हैं। वहीं, झारखंड में भाजपा के ताजा आंतरिक सर्वेक्षण ने भी पार्टी नेताओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि अगर राज्य में गठबंधन हुआ, तो भी पूर्व की तरह 12 संसदीय सीटों पर भाजपा की जीत होगी। लेकिन, किसी कारण से गठबंधन नहीं हुआ, तो सभी 14



संसदीय सीटों पर पार्टी की जीत होगी। बताया गया कि विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के प्रखंड स्तर पर

सर्वे किया गया। पार्टी का कहना है कि सर्वे में आम लोगों के साथ-साथ भाजपा व अन्य राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी राय जानी गई। वर्ष 2019 संसदीय चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित राजमहल और सिंहभूम संसदीय सीटों पर क्रमशः झामुमो और कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इस बार इन दोनों सीटों पर जीत के लिए भाजपा

ने मजबूत अभियान चलाया है। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 माह से इन क्षेत्रों में सघन अभियान चला रहा है। सर्वे में कहा गया है कि इन दोनों सीटों पर पहले से स्थिति सुधरी है, पर जीत अब भी दूर है। भाजपा ने आं तरिक सर्वे में राज्य की 14 संसदीय सीटों में से नौ को पहले नंबर पर रखा है, यहां हर हाल में जीत पक्की बताई गई है।



दुनिया के सामने संतुलन बनाना चुनौती

न्यूयॉर्क, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। भारत ने इजरायल और हमास के हिंसक संघर्ष को खत्म करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मंच पर भारत उन 153 देशों में शामिल रहा, जिन्होंने पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में बीते दो महीने से अधिक समय से जारी युद्ध रोकने की वकालत कर रहे हैं। इजरायल और अमेरिका सरीखे देशों के मजबूत प्रतिरोध के बावजूद भारत ने युद्धविराम प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत का रूख स्पष्ट करते हुए संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, टकराव बढ़ने के इस कठिन दौर में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती फैसलों के बीच सही संतुलन कायम करना है।

उन्होंने हमास और इजरायल के टकराव को असाधारण और कठिन समय करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि और भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, 193 सदस्यीय यूएनजीए में भारत ने महासभा में अभी अपनाए

अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया

पेंटागन का बयान

वॉशिंगटन, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में लगातार गहराई और मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर बहुत फोकस किया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ी प्रगति की है और आने वाले समय में भी वह सैन्य संबंधों में और प्रगति करने को लेकर आशान्वित है।

दोनों देशों के लिए यह साल पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने एक प्रेस ब्रांन्फ़ेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'हम रक्षा स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों की बहुत सराहना करते हैं। हम भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को

इजरायल-हमास सीजफायर पर भारत, महासचिव गुटेरस ने पहली बार दिखाई ताकत

गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा, यूएनजीए महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया है। महासभा ने इस पहल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीरता और जटिलता को रेखांकित किया है।

यूएन के 78 साल के इतिहास में कोवल 10 बार हुई यह खास घटना

गौरतलब है कि यूएनजीए के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 के तहत लिखा गया महासचिव गुटेरस के 6 दिसंबर के पत्र का भी जिक्र किया गया। खास बात यह कि करीब छह साल पहले- 2017 में महासचिव बनने के बाद पहली बार उन्होंने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राय में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में हो, तो



महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के ध्यान में ला सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के 78 साल लंबे इतिहास में अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल बेहद दुर्लभ घटना रही है। सात दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी अतीत में ऐसे केवल 10 उदाहरण मिलते हैं, जब महासचिवों ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामले सुरक्षा परिषद में लाए गए हैं।

बता दें कि युद्धविराम का प्रस्ताव मिस्स ने पेश किया।

प्रस्ताव में 'तत्काल मानवीय युद्धविराम' की मांग की गई। मिस्स ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा, सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। ऐसा खास तौर पर, नागरिकों की सुरक्षा के मामले में होना चाहिए। प्रस्ताव में 'सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई' की मांग भी की गई। हालांकि, इजरायल ने इस प्रस्ताव में हमास का नाम शामिल न होने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

संयुक्त राष्ट्र में 10 देशों ने विरोध में मतदान किया

बता दें कि युद्धविराम के प्रस्ताव पर भारत समेत 153 देशों ने समर्थन किया। 10 सदस्य देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 23 देशों ने मतदान नहीं किया। प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में अमेरिका, इजरायल, ऑस्ट्रिया, चेकिया, र्वाटेमाला, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया,

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान ने दी प्रतिक्रिया

कहा- अब कश्मीर मुद्दा और जटिल हो जाएगा

करांची, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान खान का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीर मुद्दे को और जटिल बना देगा।

रावलपिंडी के अदियाना जेल में बंद इमरान खान ने एक संदेश के जरिए बताया कि भारतीय शीर्ष अदालत का फैसला यूएनएससी प्रस्तावों का उल्लंघन था। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे साझा किया है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा, यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय शीर्ष अदालत का फैसला सदियों से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने में मदद करने की बजाय कश्मीर मुद्दे को और अधिक जटिल बना देगा। उन्होंने बताया

नाउरू, पापुआ न्यू गिनी और पैराग्वे हैं।

गाजा में युद्ध की विभीषिका, 18 हजार से अधिक की मौत, 50 हजार से घायल

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान ने यूएनजीए में पोस्टर दिखाकर कहा कि युद्धविराम का समर्थन करने वाले देशों को हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को फोन कर हथियार डालने के लिए राजी करना चाहिए।

बता दें कि याह्या सिनवार को युद्धग्रस्त गाजा पुर्छी पर हमास का नेता माना जाता है। सात अक्टूबर को हुए हमलों के बाद इजरायल ने सिनवार को पकड़ने के साथ-साथ हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। बीते दो महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में अब तक 18 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं।

रूस-यूक्रेन जंग, 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत

वॉशिंगटन, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। अमेरिकी इंटे्लिजेंस के मुताबिक रूू-यूक्रेन जंग में अब तक 3 लाख 15 हजार रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस जंग के पहले रूसी सेना में 3 लाख 60 हजार सैनिक थे।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंग में 87% रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग ने रूसी सेना को आधुनिक बनाने के पु्तिन की कोशिशों को 15 साल पीछे धकेल दिया है। इस नुकसान से उबरने के लिए रूस अपनी सेना में रिहा हुए कैदियों को भर्ती कर रहा है। साथ ही जंग के मैदान में भी भेज रहा है।

संसद में पेश की गई रिपोर्ट

12 दिसंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जंग से जुड़ी एक रिपोर्ट संसद में पेश की। सीएनएन के मुताबिक विपक्षी

इजराइल को कोस रहे सांसद को आया हार्ट अटैक

तेल अवीव, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। तुर्किये के एक सांसद को मंगलवार रात संसद में हार्ट अटैक आ गया। 53 साल के हसन इजराइल को कोस रहे थे। घटना का वीडियो सामने आया है। बीबीसी के मुताबिक बिटमेज संसद में इजराइल-हमास जंग पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था- इजराइल भगवान की नजरो, उनके गुस्से और प्रकोप से नहीं बच सकता। इतना कहते ही वो जमीन पर गिर गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

इधर, यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली (यूएनजीए) में मंगलवार देर रात को गाजा में सीजफायर पर प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने इसके पक्ष में वोट किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 193 सदस्यीय यूएन में यूएई, सऊदी अरब समेत 153 देशों ने सीजफायर के पक्ष में वोट किया।

कैदियों को भर्ती कर रही सेना, अमेरिकी इंटे्लिजेंस का खुलासा, यूक्रेन में साइबर अटैक



पार्टी रिपब्लिकन्स ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली एडिशनल फंडिंग पर आपत्ति जताई है। इसके बाद 11 दिसंबर को खुफिया एजेंसी ने यह रिपोर्ट कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद भवन) को भेजा। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को एडिशनल फंड देना चाहते हैं।

इस बीच मंगलवार देर रात यूक्रेन के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ।

इजराइली पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ीं

तेल अवीव, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। मिस्टर सिस्कोरिटी के नाम से प्रसिद्ध इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है। हमास के हमले के कारण बंद इजराइली कोर्ट दो माह बाद 4 दिसंबर से फिर से एक्शन में आ गई हैं। कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे रिश्तत के एक और धोखाधड़ी के 3 केसों की सुनवाई फिर से शुरू कर दी है। 4 साल पहले शुरू हुए इन केसों को नेतन्याहू के वकील अब कोर्ट से सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि युद्ध चल रहा है, इसलिए उनके (नेतन्याहू) पास तैयारी करने का समय नहीं है। इजराइली पीएम गठबंधन, वॉर कैबिनेट और पार्टी सभी मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

एक सर्वे में सामने आया है कि इजराइल के 75% लोगों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू को

इससे इंटरनेट और कम्युनिकेशन कट गया। क्रीवस्टार नेटवर्क 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंटरनेट देता है। साइबर अटैक के बाद ये सभी लोग बिना इंटरनेट रह रहे हैं। सिस्कोरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन (एसबीयू) को शक है कि इस हमले की पीछे रूस का हाथ है। इस मामले में जांच हो रही है।

घुटने टेकने की बात पर भड़के जेलेंस्की

व्हाइट हाउस पहुंचे जेलेंस्की ने कहा- कई देश कह रहे हैं कि यूक्रेन घुटने टेक दे और रूसी कब्जे की स्वीकार कर ले। ये बात बहुत गलत है ऐसा कहने वाले लोग पागल हैं। यूक्रेन क्यों हार मान जाए, यहां लोग रहते हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, परिवारों की यादे हैं। हम अपनी जमीन आतंकियों को नहीं देंगे।

अभी या फिर एक बार युद्ध खत्म हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बंधकों के परिजन भी पीएम पर सवाल उठा रहे हैं।

वहीं, अधिकारियों का कहना है कि गाजा में सैन्य अभियान और संघर्ष विराम के फैसले में नेतन्याहू की भूमिका नहीं है। इजराइली अधिकारियों का दावा है कि आईटीएफ से जुड़े हुए सारे फैसले रक्षा मंत्री योगेव गैलेंट करते हैं। इजराइली सेना के दो पूर्व जनरल बेन्नी गेंज और गेडी आइसेनकोट शामिल होते हैं। वॉर कैबिनेट के 5 लोगों के कोर ग्रुप में नेतन्याहू दरकिनार हो गए हैं।

निमिषा प्रिया की मां को यमन जाने की इजाजत

तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। अब निमिषा की मां उसे बचाने के लिए वहां जाकर ब्लड मनी सैटलमेंट करेंगी। यानी बेटी की जान बचाने के लिए मां मारे गए शख्स के परिवार को मुआवजा देकर मामले को सुलझाने और निमिषा की सजा माफ करवाने की कोशिश करेंगी।

कई इस्लामी देशों में यह कानून है कि मारे गए (हत्या के जरिए) शख्स का परिवार दोषी के परिवार से पैसा लेकर माफ़ी दे सकता है। इसे ही ब्लड मनी कहा जाता है। अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो इसकी जानकारी वहां की अदालत को एफिडेविट के जरिए देनी होती है। इसके बाद कोर्ट दोषी की सजा माफ करते हुए उसकी रिहाई का आदेश देता है।

7 साल से जेल में कैद भारतीय महिला

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया 7 साल से यमन जेल में कैद है। वह केरल की रहने वाली हैं। निमिषा ने यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की थी।

ब्लड मनी सैटलमेंट करके बेटी की जान बचाने की कोशिश करेंगी



2017 में उन्हें तलाल अब्दो मेहदी नाम के शख्स के कथित रूप से बेहोशी का इंजेक्शन देकर मारने का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से निमिषा की मां यमन जाकर उसे बचाने की कोशिशों में लगी गईं।

विदेश मंत्रालय ने कहा था- यमन जाना खतरनाक

निमिषा की मां ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में यमन जाने के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के उनकी यात्रा पर विचार करने का निर्देश दिया था। 2 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से यमन जाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां भारतीय राजनयिक उपस्थित नहीं हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा था- यमन में सिविल वॉर के कारण



भारतीय दूतावास को ज़िबूती में शिफ्ट किया गया है। साथ ही राजधानी सना में बनी नई व्यवस्था के साथ हमारे कोई औपचारिक संबंध नहीं हैं। इसलिए वहां हमारा डिप्लोमैटिक प्रेजेंस नहीं है। ऐसे में हम नि्वतित हैं कि आपकी (मां) देखभाल और सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी यमन जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

इस मामले पर एक नजर निमिषा करीब 12 साल पहले यमन गई थीं। उनके पति और बेटी 2014 में भारत लौट आए थे। नौकरी की वजह से निमिषा नहीं लौट सकीं थीं। दरअसल, उन्होंने यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी (मृतक) के साथ

एक हॉस्पिटल शुरू किया था।

कुछ वक्त बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट छीनकर अपने पास रख लिया। निमिषा ने जब इसकी शिकायत यमन की अर्थारिटीज से की तो तलाल ने उन्हें बताया कि वह निमिषा का पति है। अर्थारिटीज ने कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का मामला है। हम दखल नहीं देंगे। 25 जुलाई 2017 को निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन यह सोचकर दिया कि वह अपना पासपोर्ट हासिल कर लेंगी और भारत वापस आ जाएंगी, लेकिन तलाल की मौत हो गई। निमिषा ने एक और शख्स की मदद से तलाल के शव को ठिकाने लगा दिया, लेकिन चार दिन बाद ही मामले का खुलासा हो गया और निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा को सजा-ए-मौत सुनाई गई। उनके सहयोगी को ताउम्र जेल की सजा सुनाई गई। तब से यह मामला चल रहा है।

10 विदेशी संसदों में भी हो चुकी सुरक्षा चूक

लंदन, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी के दिन आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूद गए। युवकों ने अपने जूतों में कोई स्प्रे छिपा रखा था। वह सदन की बेंच पर कूदने लगे और इस दौरान सदन में पीली गैस फैलने लगी। पूरे सदन में अफरा-तफरी का माहौल था। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया। कुछ ने इसकी पिटाई भी की। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया।

ये हमला उस दिन हुआ देश में 2001 में हुए संसद हमले की 22वीं बरसी है। पुरानी संसद की

इमारत में 13 दिसंबर, 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी।

लंदन में 22 मार्च 2017 को वेस्टमिंस्टर पैलेस (ब्रिटिश संसद) के बाहर आतंकी हमला हुआ था। 53 साल के खालिद मसूद नाम के एक शख्स ने अपनी कार से फुटपाथ पार करते हुए संसद में घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान उसकी कार वेस्टमिंस्टर ब्रिज से टकरा गई थी। हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी

जबकि करीब 50 लोग घायल हुए थे। मसूद ने एक पुलिस अधिकारी पर भी चाकू से हमला किया था। हालांकि, बाद में एक पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया था। मसूद ने अपने आखिरी टेक्स्ट मैसेज में कहा था कि वह मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों में पश्चिमी देशों की सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए जिहाद छेड़ रहा है। जिस वक्त हमला हुआ, उस समय संसद के अंदर 200 सांसद मौजूद थे। सभी को सुरक्षा के लिहाज संसद भवन में बंद कर दिया गया था। वहीं पीएम थरेसा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। श्रीलंका में

1987 में संसद पर ग्रेनेड डाला हुआ था। 18 अगस्त को हमलावर ने उस कमरे में दो ग्रेनेड फेंके थे, जहां संसद सदस्य बैठक कर रहे थे। ग्रेनेड उस मेज से उड़कर गिरे थे, जहां श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेआर जयवर्धन और प्रधानमंत्री रणसिंघे प्रेमदासा बैठे थे। धमाके में एक संसद सदस्य और एक मंत्रालय सचिव की मौत हो गई थी।

पुलिस जांच में पता लगा था कि हमला प्रतिबंधित जनता विमुक्ति फेरामुना (जेवीपी) संगठन के एक सदस्य ने किया था। वो उस समय देश में विद्रोह कर रहा था।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, हैदराबाद केंद्र में ‘भारतीय भाषा दिवस’ कार्यक्रम संपन्न



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के हैदराबाद केंद्र द्वारा प्रसिद्ध तमिल महाकवि, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारतीय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘भारतीय भाषा दिवस’ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उस्मानिया विश्वविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. शुभदा वाजपे उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हैदराबाद की वरिष्ठ सदस्या डॉ. एस. राधा ने की। इस अवसर पर हैदराबाद केंद्र द्वारा आयोजित 466वें नवीकरण पाठ्यक्रम महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले से आए हिंदी अध्यापक भी शामिल रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो. शुभदा वाजपे ने भारतीय भाषाओं के महत्व और भारत की भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता के संदर्भ में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भारती एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश है। हर भाषा की अपनी संस्कृति होती है, जो

उसकी विशेष पहचान होती है। भारत की भाषाई भिन्नता को बरकरार रखते हुए हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्त भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अनुवाद के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि हम अनुवाद के माध्यम से एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा के लोगों तक साझा कर सकते हैं। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए डॉ. एस. राधा ने सुब्रमण्य भारती के

आए माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभागी भी शामिल रहे, जिसमें से श्रीमंत शेठके, कदम, श्रीमती जे. एच. रितुपुकर, यशवंत मस्के, भोपाले, दशरथ चौहान आदि ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अपने विचार रखे। अतिथि प्रवक्ता के रूप में केंद्र पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक पंकज सिंह यादव ने भाषा की भूमिका रेखांकित करते हुए कहा कि भाषा केवल बातचीत या विचारों के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका संबंध गहरे स्तर पर हमारे देश और लोकतंत्र से भी है। इस संदर्भ में उन्होंने भाषा के संदर्भ में महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के भाषा के संदर्भ में व्यक्त विचारों को भी साझा किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के निदेशक प्राध्यापक पंकज सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर केंद्र के प्रशासनिक सदस्य सज्जित तिवारी तथा शेख मस्तान वली उपस्थित थे।

हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहूंगा: हरीश राव

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। पूर्व मंत्री हरीश राव ने आज कहा कि प्रदर्शन के अलावा आधा प्रदर्शन नहीं जानते। विधायक सुनीता लक्ष्मी रेड्डी के नेतृत्व में मंदक जिले के नरसापुर में आयोजित बीआरएस पार्टी की आभार बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, “अगर बीआरएस सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद आवास घोटेले में मामले दर्ज किए गए होते, तो कांग्रेस पार्टी के आधे नेता जेल में होता। केसीआर ने समझाए पैदा करने के बजाय राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने संसद में गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया और संसद में सुरक्षा की कमी पर नाराजगी व्यक्त की। “अगर केंद्र सरकार संसद की सुरक्षा नहीं करती तो वह लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकती है? उन्होंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए और सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हाल के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की विधायक उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मी रेड्डी की जीत सुनिश्चित करने के लिए नरसापुर के लोगों के सामने सिर झुका रहे हैं।

सीपीआई (एम) ने सरकार से गांवों तक बस सेवा बढ़ाने का आग्रह किया

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। राज्य की सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत पर खुशी व्यक्त करते हुए, सीपीएम राज्य समिति की बैठक में आज राज्य सरकार से आग्रह किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा करने में पहचान पत्र बनाना बाधा नहीं बनना चाहिए। समिति ने चेन्नई की सीतारामुलु की अध्यक्षता में हैदराबाद में राज्य पार्टी मुख्यालय एमबी भवन में आयोजित अपनी राज्य समिति की बैठक में इस आग्रह का एक प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य बीवी

राघवुलु और केंद्रीय समिति से ए विजयराघवन ने भी हिस्सा लिया। अपने प्रस्ताव में, पार्टी ने कहा कि नवगठित तेलंगाना राज्य सरकार ने आरटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है और कहा कि आरोग्यश्री योजना की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। यह जानकर खुशी हुई कि छह में से दो गारंटियां नई सरकार के गठन के तुरंत बाद लागू की गईं। लेकिन चूंकि राज्य के लगभग 4,00,00 गांवों में अभी भी आरटीसी बस सुविधा नहीं है, इसलिए ग्रामीण गरीब महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलने की संभावना नहीं है। मुफ्त बस यात्रा सुविधा पल्लू वेलुगु, यात्री बसों और एक्सप्रेस बसों तक सीमित होने के साथ, लंबी दूरी

अनाज खरीदी में कोई कटौती न हो : डॉ. पालवाई हरीश बाबू



सिरपुर कागजनागर, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। सिरपुर विधायक डॉ. पालवाई हरीश बाबू ने आज मंडल केंद्र में दहेगांव प्राथमिक कृषि साख संध के अंतर्गत स्थापित धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा बेचे गए अनाज से अब पहले की तरह छुटकारा नहीं मिल पा रहा है।

सुझाव है कि कृषि, सहकारिता और राजस्व अधिकारी समन्वय बनाकर काम करें और बिना किसी कटौती के किसानों से अनाज खरीदी और किसान को पूरी राशि का भुगतान भी करें। सभी अधिकारियों से किसानों की सेवा में जुटे और किसानों के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त

प्रथम पृष्ठ का शेव भाग...

संसद हमले की ...

लोकसभा सांसद दानिश अली- विजिटर गैलरी से लोगों के कूदने के बाद हाउस में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद दोनों को सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़ लिया। फारुक अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस)- ये बहुत बड़ा सिक्वोरिटी ब्रीच है। ये कैसे हुआ, वो कैसे अंदर आए, कैसे उनके पास वो सब चीजें थीं, जिससे उन्होंने कनेक्टर वगैरह खोला। इस पर ग्रह मंत्रालय को फौरन ध्यान देना चाहिए। इसमें सबको खतरा है, खासकर प्रधानमंत्री को खतरा है। इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। नई पार्लियामेंट है, इतनी सिक्वोरिटी है, ये देखना जरूरी है।

डिप्ल यादव (सपा)- जो भी लोग संसद में आते हैं, चाहे वे विजिटर्स हों या पत्रकार, वे टेग नहीं रखते...। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है। लोकसभा के अंदर कुछ भी हो सकता था। शशि थरूर (कांग्रेस)- बात यह है कि इन लोगों को स्पष्ट रूप से रूलिंग पार्टी के एक मौजूदा सांसद द्वारा प्रायोजित किया गया था। ये लोग स्मोक गैस संसद के अंदर तक ले आए। यह सुरक्षा में गंभीर चूक दर्शाता है। उन्होंने न केवल स्मोक गैस चलाई, बल्कि कुछ ऐसे नारे भी लगाए, जो हममें से कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुराने भवन की व्यवस्थाओं की तुलना में नया भवन बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया। मनोज कुमार झा (आरजेडी)- इसे घटना नहीं, दुर्घटना कहें। 22 साल पहले जब संसद पर हमला हुआ था तब पक्ष और विपक्ष एक था, आज भी है, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि कोई इसे स्वीकार करके जवाब दे सके, ऐसा नहीं हो रहा। यह एक सिक्वोरिटी लैप्स है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रीम स्टेप मत लीजिए कि अब कोई विजिटर आना ही नहीं या पत्रकार घुसंगे ही नहीं। चाक चौबंद व्यवस्था करिए। इस तरह की घटना हमें झुका नहीं सकती। टीएमसी (आफिशियल ट्विटर हँडल)- हमारी सांसद महोदया मोइना को संसद से निष्कासित कर दिया गया। उन पर कथित रूप से

परमादेश या निरंतर परमादेशों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को व्यापक रूप से शक्तिशाली बनाता है। इस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति या सरकार को रिट और आदेश जारी कर सकने का अधिकार मिला है। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश होते हुए द्विवेदी ने कहा कि 2018 का आदेश बहुत सारी समस्याएँ पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट की धारा 226 के तहत शक्ति को इस तरह कम किया जा सकता है। पीठ ने उनके तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि पक्षों की चूक के कारण मामले नहीं उठाए जाते, अदालत कह सकती है कि रोक किसी विशेष तारीख तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि 2018 के फैसले में जो सिद्धांत दिया गया है, वह इस आशय का है कि रोक ऑटोमैटिक रूप से निस्त हो जाएगी, जिसका अर्थ होगा कि रोक हौनी चाहिए या नहीं, इस पर न्यायिक विचार किए बिना रोक का स्वतः निस्त होना।

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश होते हुए द्विवेदी ने कहा कि 2018 का आदेश बहुत सारी समस्याएँ पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट की धारा 226 के तहत शक्ति को इस तरह कम किया जा सकता है। पीठ ने उनके तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि पक्षों की चूक के कारण मामले नहीं उठाए जाते, अदालत कह सकती है कि रोक किसी विशेष तारीख तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि 2018 के फैसले में जो सिद्धांत दिया गया है, वह इस आशय का है कि रोक ऑटोमैटिक रूप से निस्त हो जाएगी, जिसका अर्थ होगा कि रोक हौनी चाहिए या नहीं, इस पर न्यायिक विचार किए बिना रोक का स्वतः निस्त होना।

स्वतंत्र

वार्ता

Email :

svaarth2006@gmail.com

svaarth2006@gmail.com

svaarth2006@yahoo.com

Epaper :

epaper.swatantraavarta.com

For Advertisement :

swadds1@gmail.com

राष्ट्रीय स्तर पर दमरे के सात कर्मी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से होंगे सम्मानित नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदान करेंगे पुरस्कार



डी.एस. रामाराव



सी.एच. दिनेश रेड्डी,



मल्लेला श्रीकांत



सी. शिवकुमार कश्यप



टी. प्रत्युषा



टी. नटराजन



वी.वी. रंगया

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने सात पुरस्कार प्राप्त करके एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और उन्हें ‘अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2023’ से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 15 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कर कमलों से प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सात कर्मचारियों में डी.एस. रामाराव, उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण, काजीपेट, दक्षिण मध्य रेलवे हैं। इन्होंने काजीपेट-बल्लारहाह के बीच विभिन्न सेशन में तीसरी लाइन के कार्यों को कमीशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख रूप से 9 याइ की रिमांडिलिंग शामिल थी तथा गैर-अंतर्धान कार्य के दौरान 245 टर्नआउट डाले/हटाए गए। इसी क्रम में सी.एच. दिनेश रेड्डी, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण चल स्टॉक, विद्युत लोको शेड, विजयवाड़ा, दक्षिण मध्य रेलवे इलेक्ट्रिक लोको शेड, विजयवाड़ा के प्रभारी हैं। श्री रेड्डी परेशानी मुक्त गाड़ी परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लोकोमोटिव की संरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार पर जोर दिया। मल्लेला श्रीकांत, मंडल

परिचालन प्रबंधक/सिकंदराबाद/दमरे (अब उप निदेशक/माल लदान एवं उर्वरक/रेलवे बोर्ड) ने एसएमएस द्वारा स्वचालित अपवादा अलर्ट के साथ मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेन-ईवेंट्स के डिजिटल प्रसारण को विकसित किया है। इससे साइडिंग पर लदान करने स्थिति पर नज़र रखने और मालगाड़ियों की रीयल टाइम निगरानी में मदद मिली है।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष ईआईई-कवच इंटरफ़ेस की तैनाती में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके कारण 13 मार्ग किलोमीटर के स्वचालित सेक्शन सहित 1002 मार्ग किलोमीटर में 10 स्टेशनों पर कवच की त्वरित तैनाती हुई। टी. प्रत्युषा, महिला सब-इंस्पेक्टर, रेल सुरक्षा बल, निजामाबाद ने मर्डर केस के दो अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। मानव तस्करी में शामिल अपराधी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टी. नटराजन, मुख्य टिकट निरीक्षक/वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक स्कॉड/सिकंदराबाद अपने अथक और समर्पित प्रयासों से टिकट जांच में उत्कृष्ट निष्पादन किया है। आपने गहन जांच करते हुए बिना टिकट और अनधिकृत यात्रा करने वालों पर प्रतिबंध लगाया।



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। एमएलसी कविता ने बुधवार को सड़क और भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकटर रेड्डी से मुलाकात की, जिनका बीमारी के कारण यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। कविता ने डॉक्टरों से वेंकटर रेड्डी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पड़ताल की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री जी कुछ दिनों से गले में खराश से परेशान हैं। मंगलवार को दिल्ली से लौटते पर गंभीरता बढ़ने के कारण उन्हें सोमाजीगुडा के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री की जांच करने वाले डॉक्टरों ने उन्हें दो दिनों तक अस्पताल में रहने की सलाह दी। अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।

सड़क दुर्घटना में युवक की मौत

निर्मल, 13 नवंबर (स्वतंत्र वार्ता)। निजामाबाद जिले के आर्मुर् बाल कोंडा के बीच मंगलवार की रात एक सड़क दुर्घटना में भैंसा शहर के एलंत्रवार वेंकटर (25) नामक युवक की मौत हो गई। परिजनों की सूचना अनुसार वेंकटर डीजे वाहन पर समारोह में शामिल होने के लिए बोलेरो वाहन से निजामाबाद के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक ट्रक से वाहन के टकराने से घटना स्थल पर इसकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर को हल्की चोट लगी है।

कपास बिक्री का शुभारंभ



मदनूर 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता) (स्वतंत्र वार्ता)। स्थानीय कृषि बाजार समिति कार्यालय मैदान में बुधवार के दिन जुकल विस क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक तोटा लक्ष्मी काता राव ने किसान, जिनिंग मालिक, कमीशन एजेंट, स्थानिक नेता के समक्ष श्रीफल फाइनर कपास बिक्री का शुभारंभ किया गया। विधायक कपास का बिक्री प्रारंभ करते ही कपास खरीदार द्वारा एक कुंतल कपास 7100 रुपये में खरीदी किया गया। इस समय स्थानिक कृषि बाजार समिति अध्यक्ष संगमेश्वर, कृषि बाजार समिति सचिव विठ्ठल, सत्यम, कार्यालय के कर्मचारी के साथ अन्य कांग्रेस पार्टी नेता उपस्थित थे।



बरंगर सेना, तेलंगाना अध्यक्ष एन.आर. लक्ष्मण राव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कमला अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, एनपीए राजेंद्र नगर के सामने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के लिए आयोजित रक्तदान शिविर में सक्रिय रूप से भाग लिया। सचिव और सीईओ डॉ. सुमन जैन के साथ अस्पताल में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस मौके पर रजनी श्रीरामोजू अध्यक्ष महिला मोर्चा, सूर्य शुकला महासचिव, मनोज मोगलगिड्डी अध्यक्ष ग्रेटर हैदराबाद, नरेश युवा सचिव और सदस्य उपस्थित थे।



मैदानखा चौक स्थित बालाजी मंदिर में 23 दिसंबर को आयोजित होने वाले वैकुंठ एकादशी उत्सव के लिए महेश बेंक के चेयरमैन रमेश कुमार बंग को आमंत्रित करते हुए राधेश्याम गुप्ता, राधेश्याम मंडोतिवार, मधुसूदन अग्रवाल, राजेंद्र पिप्पी, रमनाचारी महाराज।

हैदराबाद पुलिस ड्रग माफिया पर कार्रवाई तेज करेगी : श्रीनिवास रेड्डी

नए सीपी ने कार्यभार संभाला और ड्रग तस्करों को दी चेतावनी

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। बुधवार को बंजारा हिल्स स्थित पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभालने वाले हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद पुलिस ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करेगी और संदिग्धों से सख्ती से निपटेगी। मीडिया से बातचीत में हैदराबाद सीपी ने कहा कि जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन में लिप्त हैं, उन्हें राज्य छोड़कर चले जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम ड्रग माफिया को अस्तित्व में नहीं आने देंगे। लोगों को इस खतरे को खत्म करने में पुलिस के साथ साझेदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां टॉलीवुड के लोग नशीली दवाओं के मामलों में पकड़े गए थे और हम निश्चित रूप से उद्योग और पब, स्टार होटलों और रिसॉर्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य हैदराबाद को नशा मुक्त शहर



बनाना है और इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना है।" श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पुलिस महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी और शी टीमें को और मजबूत करेगी और उन्हें और अधिक कुशल बनाएगी। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अवांछनीय घटनाओं के मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया टीम को मजबूत किया जाना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी पुलिसिंग में भी

सुधार किया जाना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी टीमों को भी मजबूत किया जाएगा, महिलाओं को परेशान करने, छेड़छाड़ करने और रैपिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में मित्रवत पुलिसिंग का उपहास उड़ाया गया है, हर किसी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना एक नुकसान है। हम कानून का पालन करने वाले लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ता तो हम सख्त होंगे। इस अवसर पर विक्रम सिंह मान एडिशनल सीपी एलएंडओ, पी. विधु प्रसाद एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच, श्रीमती जे.परिमाला हाना नूतन ज्वाइंट सीपी एडमिन, गजाराव भूपाल ज्वाइंट सीपी क्राइम एंड एसआईटी, जोएल डेविंस डीसीपी प्रोथिम क्षेत्र और टी.रादेश मुरली डीसीपी एसएमआईटी आदि उपस्थित रहे।

पीआरएसआई ने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी को दी बधाई

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) हैदराबाद चैप्टर ने ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली हाल ही में स्थापित कांग्रेस सरकार में सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री के रूप में पदभार संभालने पर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को हार्दिक बधाई दी। यह सम्मान रविवार को बुलाई गई कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान प्रदान किया गया, जहां सदस्यों ने अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार पोंगुलेटी की नियुक्ति की मुख्यमंत्री ने एक विवेकपूर्ण पसंद के रूप में सराहना की है, जिन्होंने एक अनुभवी राजनेता और एक कुशल संचारक दोनों के रूप में उनकी दोहरी ताकत को पहचाना। प्रस्ताव में कहा गया है कि आई और पीआर विभाग, जिसे सरकारी नीतियों और पहलों के प्रसार के



लिए प्रमुख माध्यम माना जाता है, पोंगुलेटी के नेतृत्व में फलने-फूलने के लिए तैयार है। पीआरएसआई हैदराबाद चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. एस. रामू ने आई और पीआर विभाग को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में श्री पोंगुलेटी की क्षमता के बारे में आशा व्यक्त की। डॉ. रामू, जो मंत्री के रूप में खम्मम जिले से भी संबंधित हैं, ने जनता के प्रति श्री पोंगुलेटी के सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण की पुष्टि की। पीआरएसआई हैदराबाद के सचिव के. यादगिरी ने नवनियुक्त आई और पीआर मंत्री को बधाई देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की योजना की घोषणा की।

भारतीय नौसेना ने 'नेवी बैंड कॉन्सर्ट' का आयोजन किया



रक्षा मंत्री 17 को वायु सेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा करेंगे

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेटों के ग्री-कमीशन प्रशिक्षण के सफल समापन को चिह्नित करने के लिए, वायु सेना अकादमी (एएफए), डुड्डीगल में 212 अधिकारियों के पाठ्यक्रम की संयुक्त स्नातक परेड (सीजीपी) 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीजीपी के मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी (आरओ) होंगे। समारोह में फ्लाइट कैडेटों, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के साथ-साथ मित्र विदेशी देशों के अधिकारियों को 'विंस' और 'ब्रेवेट्स' की प्रस्तुति शामिल है।

'विंस' और 'ब्रेवेट्स' परस्कार प्रत्येक सैन्य एविएटर के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और प्रशिक्षण की एक कठिन अवधि की परिणति है। फ्लाइटिंग क्राउन के फ्लाइट कैडेट, ऑर्डर-ऑफ-मेरिट में प्रथम स्थान पर रहेंगे, उन्हें

समग्र प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' और 'राष्ट्रपति पट्टिका' से सम्मानित किया जाएगा। कैडेट को परेड की कमान संभालने का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। आरओ ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में से

संसद सुरक्षा उल्लंघन की व्यापक जांच होनी चाहिए : नागेश्वर राव

खम्मम, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस लोकसभा नेता और खम्मम सांसद नामा नागेश्वर राव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार को संसद में सुरक्षा उल्लंघन एक व्यापक बयान जारी करने की मांग की। संसद की घटना पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिस्ला के नेतृत्व में बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद सांसद ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पीकर से घटना की व्यापक जांच कराने और तथ्य संसद के सामने लाने को कहा है। केंद्र सरकार ने कुछ समय तक अखबारों में छपी इस खबर पर ध्यान नहीं दिया कि हमले की आशंका है। नागेश्वर राव ने कहा कि उनका मानना ​​है कि यह घटना सुरक्षा विफलता के कारण हुई। ठीक 22 साल पहले आज ही के दिन संसद के बाहर आतंकी हमला हुआ था और कई लोग मारे गए थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि यह घटना संसद के अंदर हुई थी। उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा की ऊंचाई कम होने के कारण हमलावर सदन के बीच में कूद गए और रंगीन धुआं छोड़ा और कहा कि वह उस समय संसद के अंदर थे।

पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। पूर्व मंत्री और बीआरएस पार्टी के विधायक सीएच मल्ला रेड्डी के खिलाफ शमीरपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि मल्ला रेड्डी ने आदिवासियों की 42 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। पुलिस ने मल्ला रेड्डी की शिकायत पर एससी, एसटी अत्याचार

प्रजा भवन डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क का आधिकारिक आवास

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन, बेगमपेट में आवासीय भवन को उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू को उनके आधिकारिक आवासीय आवास के रूप में आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कथित तौर पर जुबली हिल्स में अपने आवास में रहना पसंद कर रहे हैं। इसलिए प्रजा भवन उप मुख्यमंत्री को आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को प्रजा भवन उपमुख्यमंत्री को सौंपने का निर्देश दिया है। बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान, प्रजा भवन, जिसे प्रगति भवन कहा जाता था, में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कैप कार्यालय था।

कारगिल से कन्याकुमारी तक लगातार तीसरा अभियान पूरा किया



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। शहर स्थित साइकिलिंग समूह 'हैदराबाद साइक्लिस्ट ग्रुप' (एचसीजी) ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारतीय साइकिलिंग इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने नवंबर से दिसंबर 2023 तक कारगिल से कन्याकुमारी तक 3800 किलोमीटर के अभियान पर विजय प्राप्त की, जिससे देश में साइकिल चलाने के लिए एक नया मानक स्थापित हुआ। एचसीजी के संस्थापक और उत्साही साइकिलिंग समर्थक रविंद्र नंदनूरी के नेतृत्व में, यात्रा 21 नवंबर को कारगिल युद्ध स्मारक पर शुरू हुई। चरम

मौसम को सहते हुए, टीम ने अत्यधिक लचीलेपन और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए, 13 दिसंबर को विजयी रूप से अपना अभियान समाप्त किया। यह उपलब्धि केवल विशाल दूरी तय करने के बारे में नहीं है; यह स्वस्थ भारत के लिए साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के एक बड़े मिशन का प्रतीक है। उल्लेखनीय रूप से, यह इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में एचसीजी की लगातार तीसरी जीत है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली टीम बन गई है। इसके अलावा, हैदराबाद के 39 सवारों ने केवल दो वर्षों में मार्ग पूरा

किया, जो एचसीजी के प्रयासों से प्रेरित साइकिल चलाने के शौकीनों के बढ़ते समुदाय को उजागर करता है। रविंद्र नंदनूरी ने साइकिलिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हुए इस चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद यात्रा के माध्यम से टीम का नेतृत्व किया। एचसीजी की ऐतिहासिक जीत भारत की साइकिलिंग कथा में एक स्थायी विरासत स्थापित करती है, साइकिल चालकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और एक स्वस्थ, अधिक सक्रिय भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।

राष्ट्रपति के वार्षिक प्रवास को लेकर सीएस ने की बैठक



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 23 दिसंबर तक हैदराबाद के अपने वार्षिक प्रवास पर रहेंगी। इसी को लेकर तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने राष्ट्रपति की यात्रा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से

उचित समन्वय सुनिश्चित करने और उचित तरीके से विस्तृत व्यवस्था करने को कहा। राष्ट्रपति मुर्मू पांच दिनों के लिए हैदराबाद में रहेंगे और 23 दिसंबर को रवाना होंगे। पुलिस विभाग को पर्याप्त सुरक्षा, यातायात और बंदोबस्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य, आरएंडबी, नगरपालिका, ऊर्जा और अन्य

लाइन विभागों को भी ब्लू बुक के अनुसार फुलप्रूफ व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीजीपी रवि गुप्ता, विशेष मुख्य सचिव सुनील शर्मा, सचिव जीएडी शेषाद्री, सचिव स्वास्थ्य एसएएम रिजवी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सिकंदराबाद-दानापुर 7 जनवरी तक वाराणसी, प्रयागराज नहीं जाएगी

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। उत्तर मध्य रेलवे पर प्रयागराज स्टेशन के प्रमुख उन्नयन कार्य और प्लेटफार्म नंबर 9 और 10 को बंद करने के कारण सिकंदराबाद-दानापुर-सिकंदराबाद ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 12791 सिकंदराबाद-दानापुर 27 नवंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक मानिकपुर, मुगलसराय होकर गुजर रही है। यह ट्रेन प्रयागराज और वाराणसी नहीं जा रही है। इसी क्रम में ट्रेन नंबर 12792

कांग्रेस, बीआरएस, एमआईएम एक ही पार्टियां : डीके अरुणा

हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम पार्टियां एक ही हैं और उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव उसी का प्रमाण है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार से चुनावी वादों को लागू करने की मांग की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर वादों को कुचलने का प्रयास किया जाएगा, उन्होंने मांग की कि स्थूध बंध योजना का लाभ तुरंत किसानों के खातों में जमा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं 500 रुपये के गैस सिलेंडर के इंतजार में गैस एजेंसियों के सामने लाइन लगा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्व सीएम केसीआर की सरकार के प्रति लोगों का विरोध तेलंगाना में भाजपा के संघर्ष के कारण आया। अरुणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुफ्त सुविधाओं के वादे के साथ सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने वोट शेयर और सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में अधिकांश एमपी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम को कामरेड्डी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने कुचल दिया था और कहा कि विधानसभा चुनावों ने साबित कर दिया है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चाहते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने लोगों को धोखा दिया है : केटीआर



हैदराबाद, 13 दिसंबर (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक केटी रामा राव ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे वादे करके लोगों को धोखा दिया है जिन्हें लागू करना संभव नहीं है। केटीआर ने बुधवार को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रसाद कुमार के नाम का प्रस्ताव करते हुए नामांकन पर हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कभी भी सिर पर चर्चा नहीं हुई। कैग हर साल रिपोर्ट देता

कांग्रेस शासकों के लिए एक वास्तविक खेल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में आने के दो दिनों के भीतर ऋण माफी का वादा किया था, उन्होंने पूछा कि पहली कैबिनेट बैठक में ऋण माफी और छह गारंटी की मंजूरी का क्या हुआ? उन्होंने कहा, "राज्य कर्ज के बोझ तले दब गया है और कल राज्यपाल अपने भाषण में वही पुरानी इमली की चटनी कहेंगी।" यह दावा करते हुए कि सत्तारूढ़ दल के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में 45,000 नौकरियों का वादा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि वे इसे कैसे पूरा करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था?

केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर पर कितना ध्यान सोनोवाल ने पीएम मोदी-केंद्रीय मंत्रियों के दौरे गिनाकर बताया

गुवाहाटी, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के नौ साल के कर्वांफाल के दौरान राज्य में हुए विकास पर बात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नौ साल के कार्यकाल में क्षेत्र के लिए अपनी गारंटी से अधिक काम किया है। असम के पूर्व सीएम ने बताया कि पीएम मोदी उत्तर-पूर्वी राज्यों का अबतक 64 बार दौरा कर चुके हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि सड़क, रेलवे, जलमार्ग और हवाई संपर्क सहित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नौ वर्षों में क्षेत्र के आठ राज्यों को पांच लाख

करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हवाईअड्डों की संख्या बढ़कर अब नौ से 17 हो चुकी है। सोनोवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद, प्रदर्शन, कमजोर सरकारें और घोटालों ने उनके शासन में क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने कांग्रेस पर संसाधनों को लूटने का भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने बताया कि कांग्रेस के शासन काल में मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने के लिए क्षेत्र के प्रतिनिधियों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने क्षेत्र के लोगों तक पहुंच बनाई है। खुद प्रधानमंत्री ने यहां 64 बार दौरा किया है।

उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी यहां 64 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन 60 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे पीएम मोदी ने केवल नौ वर्षों में ही कर दिखाया है। यही कारण है कि आठ उत्तरपूर्वी राज्यों में रहने वाले नागरिक पीएम मोदी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है। उत्तरपूर्वी राज्यों में विकास अच्छी सरकार के वजह से ही हो पाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपित सिम्बल द्वारा असम को ग्यांगार का हिस्सा बनाया गया तीरुप्णी पर सवाल किया तो सोनोवाल ने कहा कि उन्हें (सिम्बल) इतिहास का ज्ञान नहीं है।

सीएम विजयन ने गवर्नर से कहा, हमें धमकाने की कोशिश न करें



कोच्चि, 13 दिसंबर (एजेंसियां)। केरल के मुख्यमंत्री पिनारै विजयन ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि वह राज्य सरकार को धमकी न दें और उन्हें एक संवैधानिक प्रमुख की तरह व्यवहार करना चाहिए। मुख्यमंत्री पिनारै विजयन ने कहा, 'एक राज्यपाल को राज्यपाल की तरह काम करना चाहिए और हमें धमकी नहीं देनी चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान अवसरवादी का

सबसे अच्छा उदाहरण हैं। उनके लिए संवैधानिक प्रमुख की तरह व्यवहार करना बेहतर होगा।' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल उन बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं जो आरएसएस द्वारा आयोजित की जाती हैं। उन्होंने पूछा, क्या राज्यपाल के तौर पर उन्हें ऐसी बैठकों में हिस्सा लेना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनारै विजयन वर्तमान में 27 नवंबर से अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर

करते हुए राज्यव्यापी दौरे पर हैं। राज्यपाल ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के लिए केरल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यपाल ने कहा, 'क्या इस दौर की कोई जरूरत थी? आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोगों को अपनी आर्थिक समस्या के समाधान की जरूरत है, न कि इन दौरों की।' उन्होंने कहा कि उन्हें केरल के लिए खेद है। राजस्व केवल लांटी रिटर्की और शराब की बिक्री से उत्पन्न होता है और उन्होंने राज्य में वित्तीय संकट के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। राज्यपाल का बयान ऐसे समय आया है जब विजयन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि केंद्र केरल के लिए फंड का गला घोट रहा है और उसे ऋण लेने से रोक रहा है।